दैनिक
आदित्यवर्ण तमस: परस्तात्
नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर
3 राजधानी — मध्यप्रदेश के हालात बेहद चिंताजनक ...
4 अभिव्यक्ति — प्रतिकूलता से निपटना और उसके आगे...
6 मनोरंजन/खेल — फीस में कटौती के लिये तैयार हैं तापसी...
7 व्यापार — 12 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब...

www.navpradesh.com भोपाल, सोमवार 18 मई 2020, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष-एकादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-04 अंक-38 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए डाक पंजीयन संख्या -म प्र /भोपाल /4-468/2018-20 मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड, से एक

आज बेबाक

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौव्हान का कहना है कि कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि वह मंदिरों में पड़े स्वर्ण भंडारों को अपने नियंत्रण ले ले। इससे 76 लाख करोड़ की सहायता मिलेगी। मतलब उनके पास मंदिरों के धन का पूरा हिसाब है। मंदिरों के धन पर गिद्ध दृष्टि डालने वालों यह धन जन कल्याण में ही खर्च होता है, धर्म के प्रचार में नहीं। बेहतर होगा कि चौव्हान यह सुझाव देते कि भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के पास जो काला धन है उसे राजसात कर उसका उसका उपयोग कोरोना संकट से निपटने में किया जाए।

गरीबों, मजदूरों, किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ ट्रांसफर

सरकार ने गरीबों के लिए खोला खजाना : मुख्यमंत्री चौहान

डॉ शिशिर उपाध्याय

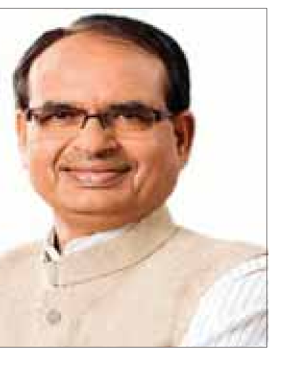

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले 45 दिनों में 2 करोड़ 94 लाख गरीबों, श्रमिकों और किसानों के खातों में 16 हजार 489 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखाते हुए शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोगों के खातों में सीधे राशि पहुंचाई। कोरोना संकट के चलते राज्य के कर राजस्व में आई कमी एवं वित्तीय संकट के बावजूद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गरीबों, मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। इससे प्रदेश के लोगों में वित्तीय तरलता बनी रही। अभी तक 6 हजार 489 करोड़ विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राशि ट्रांसफर की गयी है और 10 हजार करोड़ रुपये गेहूँ उपार्जन के लिए भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने शासन के विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा कर यह निर्णय लिया है कि जितने भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं वे सबसे पहले गरीबों मजदूरों और किसानों की योजनाओं के लिए दिये जायें। लगभग प्रतिदिन किसी न किसी योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की गई है। मध्यप्रदेश सरकार ने कोरोना संकट में प्रारंभ से ही इस रणनीति पर काम किया कि सरकारी योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा राशि लोगों के खातों में डाली जाये। सरकार ने 15 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा योजना की 2981 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। कोरोना संकट के बावजूद किसानों से गेहूँ उपार्जन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई। इस वर्ष उपार्जन में अभी तक 12 लाख 61 हजार किसानों से 87 लाख 43 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। उपार्जित गेहूं के विरूद्ध किसानों को अब तक 10 हजार करोड़ का भुगतान उनके खातों मे किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत एक लाख 78 हजार 417 हितग्राहियों को 451 करोड़, प्रधानमंत्री आवास शेष पृष्ठ 7 पर

मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मृतक मजदूर के परिवार को 14 लाख रूपए की आर्थिक सहायता

बच्चों के हम संरक्षक हैं, उनका पूरा ध्यान रखेंगे

बाहर के मजदूरों को भी एक-एक लाख की सहायता मिलेगी

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने बड़वानी जिले के नेवाली ब्लॉक के एक मजदूर परिवार में पति-पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर बच्चों को कुल 14 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कहा है कि हम उन मासूम बच्चों के संरक्षक हैं तथा उनका पूरा ध्यान रखेंगे। दिए जाने वाली राशि में से एक लाख रूपए बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए तथा 13 लाख की एफ.डी. उनके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए रहेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बच्चों के चाचा श्री राजेश से भी दूरभाष पर चर्चा कर बच्चों की समुचित देखभाल करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह अत्यंत दु:खद शेष पृष्ठ 7 पर

आज से लॉकडाउन का चौथा चरण ज्यादातर अधिकार राज्यों को मिले

31 मई तक के लिए पूरे देश में होगा लागू

अब राज्य ही तय करेंगे ग्रीन, ऑरेंज व रेड जोन

पहले से ज्यादा ढील तो दी पर शर्तों के साथ ही

नई दिल्ली/नवप्रदेश। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर देश में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। यानी सोमवार 18 मई से राज्य में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन-4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। इस चरण में पहले से ज्याद ढील तो दी गई है लेकिन यह भी शर्तों के साथ ही है। जोन निर्धारण का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। केंद्रीय सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र सरकार ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (एनडीएमए) ने इस बारे में ऑर्डर जारी किया। इसके बाद केंद्र शेष पृष्ठ 7 पर

ये सेवाएं चालू

चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल, अन्य होटल व रेस्त्रां से सिर्फ होम डिलेवरी, बिना दर्शक स्टेडियम, इंटर स्टेट बस सेवा राज्यों के बीच सहमति के आधार पर

ये सेवाएं बंद

मेट्रो और रेल सेवा, सामान्य हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे, जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग किसी तरह की आवाजाही नहीं कर सकेंगे। जरूरी सेवाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। स्थानीय प्रशासन इस बारे में जरूरी आदेश जारी कर सकता है।

बच्चों-बुजुर्गों को घर में रहना होगा

65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, पहले से बीमार लोग, ग?र्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहना होगा। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।

आरोग्य सेतु ऐप

रविवार को जारी गाइडलाइंस में होम मिनिस्ट्री ने आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भी अहम बात कही। आदेश में कहा गया है, 'ऑफिस या दूसरे कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा जरूरी है। लिहाजा, कंपनियां कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप इन्स्टॉल करने के लिए प्रेरित करें। जिला प्रशासन भी लोगों से इस ऐप को इन्स्टॉल करने की सलाह दे। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस भी करना चाहिए।'

ये राज्य पहले ही बढ़ा चुके लॉकडाउन

देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उससे लॉकडाउन का बढ़ना लाजिमी माना जा रहा था। कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की थी। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90 हजार के पार पहुंच चुकी है जिनमें से 2800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में राज्यों से सुझाव मांगे थे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें सभी राज्यों से शेष पृष्ठ 7 पर

तीसरी बार बढ़ा लॉकडाउन

यह तीसरा मौका है जब लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इससे पहले भी दो बार देश में लॉकडाउन बढ़ाया गया था और लॉकडाउन-3 की मियाद रविवार को खत्म हो रही थी। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में लॉकडाउन बढ़ाने का संकेत दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह कुछ नए रंग रूप वाला होगा। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि यह नया रंगरूप कैसा होगा? इसमें किस तरह की छूट दी जाएगी।

अच्छी खबर

लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में 8 विदेशी और देशी जमातियों की जमानत सेशन कोर्ट से नामंजूर

भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने लॉकडाउन के उल्ल्घंन के मामले में 8 विदेशी और देशी जमातियों की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। रविवार को जज अजय श्रीवास्तव ने वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये जमानत पर बहस सुनी। सरकारी वकील ने जमानत पर आपत्ति की। आरोपी साजिद करीम, करीम उल्ला, निवासी समस्तीपुर बिहार, नूर बेग, कनात बेग, मस्कट, काद्रेबेक निवासी किर्गीस्तान, कमोलिदीन उजबेकिस्तान, मदियाद कजाकिस्तान की जमानत नामंजूर करते हुए जज ने लिखा कि मामले में शुरूआती जांच चल रहीं है, इसलिए गुण दोषों पर टिप्पणी किये बिना जमानत दिया जाना उचित नहीं है। वहीं थाना पिपलानी और मंगलवारा से जेल गये 20 जमातियों की जमानत अर्जी बल न देने के कारण निरस्त की गई है। अब आरोपियों के पास सिर्फ हाईकोर्ट से जमानत का विकल्प बचा है।

निजी कंपनियों को हर क्षेत्र में एंट्री मनरेगा व स्वास्थ्य का बढ़ेगा बजट

मनरेगा के लिए होगा 40 हजार करोड़ रुपए का अरिरिक्त आवंटन

लोक उपक्रमों की संख्या होगी कम

नई दिल्ली ब्यूरो/नवप्रदेश। आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के पाँचवें और अंतिम चरण में सरकार ने रविवार को सभी क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने, लोक उपक्रमों की संख्या कम करने, मनरेगा के लिए आवंटन और स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाने तथा कंपनी कानून और दिवालिया कानूनों में बड़े बदलावों की घोषणा की। यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य तथा मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों के अपने अपने घार लौटने के कारण उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ शेष पृष्ठ 7 पर

ऐसे समझें पूरे पैकेज का गणित

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना- 1.70 लाख करोड़
- रिजर्व बैंक द्वारा घोषित- 801603 करोड़ रुपये की मौद्रिक सहायता
- गत 22 मार्च से दिये गये कर छूट से भी 7800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
- प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की थी।
- 22 मार्च के बाद घोषित कुल 994403 करोड़
- आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहली किश्त 594550 करोड़ रुपये
- दूसरी किश्त 3.10 लाख करोड़ रुपये
- तीसरी किश्त 1.50 लाख करोड़ रुपये
- चौथी एवं पांचवीं किश्त मिलाकर 48100 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।
- इस तरह कुल मिलाकर 1102650 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज 12 मई के प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद घोषित किये गये हैं।
- इस दौरान कई प्रशासनिक और विधियी संशोधनों को भी मंजूरी दी गयी है।

दिवालिया व शोधन अक्षमता कानून में होगा बदलाव

वित्तमंत्री ने कहा कि देश में कारोबार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी कानून और दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कानूनों में बदलाव किये जा रहे हैं। निजी कंपनियों को अब अपने शेयर सीधे विदेशों में सूचीबद्ध कराने का अधिकार दिया जायेगा। साथ ही गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) संबंधी नियमों में भी बदलाव किया जायेगा। अब शेयर बाजार में एनसीडी जारी करने से कंपनी को सूचीबद्ध नहीं माना जायेगा। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थितियों की वजह से कर्ज में चूक होने पर दिवालिया कानून के तहत इसे चूक नहीं माना जायेगा।

कोरोना अपडेट

देश	टोटल केस	मौत
भारत	92,239	2,911
अमेरिका	1,511,295	90,198
ब्रिटेन	240,161	34,466
इटली	224,760	31,763
स्पेन	277,719	27,650
फ्रांस	179,365	27,625
ब्राजील	233,511	15,662
बेल्जियम	55,280	9,052
जर्मनी	176,252	8,027
ईरान	120,198	6,988
नीदरलैंड	43,995	5,680
कनाडा	75,864	5,679
मैक्सिको	47,144	5,045
टर्की	148,067	4,096
स्वीडन	30,143	3,679
रूस	281,752	2,631

सुप्रीम कोर्ट का हेल्पलाइन नंबर जारी

सुबह 10 से शाम 5 बजे तक करेगा काम

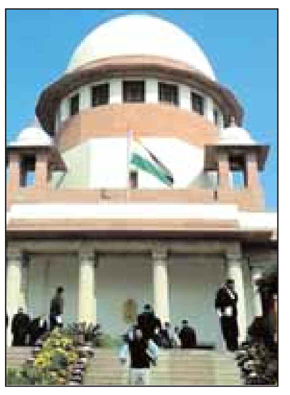

नई दिल्ली/नवप्रदेश। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान उच्चतम न्यायालय के इतिहास में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई सहित कई नये अध्याय जुड़े हैं तथा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नयी हेल्पलाइन शुरू की गयी है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने वादियों, प्रतिवादियों और वकीलों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचाने के लिए एक हेल्पलाइन टेलीफोन नंबर जारी किया है। यह हेल्पलाइन (1881) सुप्रीम कोर्ट में मामलों की ई-फाइलिंग करने का तरीका समझने या किसी तरह की दिक्कत की स्थिति में वादियों, प्रतिवादियों और वकीलों को मदद पहुंचायेगी। यह हेल्पलाइन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक काम करेगी। इससे पहले कोरोना महामारी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिनमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई, वकीलों को काला कोट और गाउन से निजात देना तथा ई-फाइलिंग की सुविधाएं शामिल हैं।

ग्रीष्मावकाश के सप्ताह को पहले ही किया कम

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के इतिहास में पहली बार सात सप्ताह के ग्रीष्मावकाश को कम करके दो सप्ताह के लिए कर दिया गया है। इस वर्ष 18 मई से पांच जुलाई तक अवकाश होना था, लेकिन नये सर्कुलर के तहत अब शीर्ष अदालत में 19 जून तक न्यायिक कामकाज होगा। अब इस साल केवल दो सप्ताह के लिए ही ग्रीष्मावकाश होगा।

घोषणा

जियो प्लेटफॉर्म्स में जनरल अटलांटिक 6598.38 करोड़ का करेगी निवेश

मुंबई । वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट की चुनौतियों से एक तरफ देश जहां सोमवार से लॉकडाउन के चौथे चरण की तरफ बढ रहा है वहीं इस दौर में मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो प्लेटफार्म्स ने एक माह से कम समय में चौथा निवेशक विश्व के अग्रणी ग्रोथ निवेशक जनरल एटलांटिक को अपने पाले में लाने का ऐलान किया। जियो प्लेटफॉर्म्स में जनरल अटलांटिक 6598.38 करोड़ का निवेश करेगी। मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्मस में रविवार को यह निवेश 4.91 लाख करोड़ रुपये के इक्विटी मूल्यांकन और 5.16 उद्यम कीमत लाख करोड़ रुपये पर करने की घोषणा हुई है। जनरल अटलांटिक को निवेश से जियो में 1.34 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी।

भोपाल में 38 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

रविवार को आई रिपोर्ट में 10 सदस्य 3 अलग-अलग परिवारों के बताए जा रहे हैं, इनमें से कुछ को पहले से ही आइसोलेट किया गया थो कुछ क्वारैंटाइन में थे

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। रविवार दोपहर को स्वास्थ्य विभाग ने शहर मे 38 कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की सूची जारी की है। इन मरीजों को मिलाकर भोपाल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1057 पर पहुंच गया है। अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर ये है कि अब तक 633 कोरोनावायरस से संक्रमित मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। राजधानी में कोरोना से संक्रमित एक्टिव मरीज 412 हैं। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि आज मिले संक्रमित मरीजों में 10 जहांगीराबाद इलाके के ही हैं। कुवैत से लौटे 6 अन्य प्रदेशों के लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटव आई है। शनिवार तक कुवैत से शेष पृष्ठ 7 पर

45 जिलो में फैला करोना, सात बचे

प्रदेश में अब तक 52 में से 45 जिलों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है। केवल राजगढ़, छतरपुर, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिंगरोली और निवाड़ी जिले कोरोना से बचे हैं। शनिवार को उमरिया में पहला संक्रमित मिला। प्रदेश में एक मई को 33 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 16 दिन में यह 12 जिलों में और फैल गया। हाल में जिन नए जिलों में कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें उमरिया, दमोह, सिवनी, पन्ना, मंडला, गुना, डिंडोरी, अशोक नगर, बैतूल आदि जिले शामिल हैं।

गरमा-गरम

समाधान लॉकडाउन के कारण स्कूल-कॉलेज बंद होने के मद्देनजर सरकार ने लॉन्च की योजना

अब पीएम-ई विद्या से पढ़ेंगे पहली से 12वीं तक के बच्चे

ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हर कक्षा के लिए होगा एक अलग चैनल

नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना माहामरी के कारण लॉकडाउन से स्कूल एवं कॉलेजों के बन्द होने से पढ़ाई नहीं होने की वजह से अब ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिये 'पीएम ई-विद्या' की योजना बनाई है। इसके लिए देश के सौ विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है तथा हर क्लास से लिये एक चैनल खोलने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की योजना के तहत एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफार्म कार्यक्रम का खुलासा करते हुए यह जानकारी दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने इस घोषणा का शेष पृष्ठ 7 पर

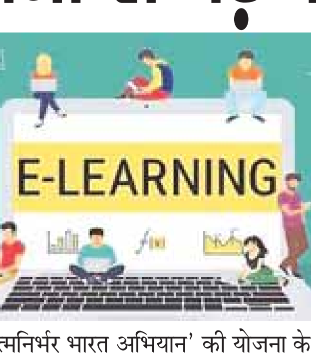

ऐसे समझें पूरी योजना

- स्वयं प्रभा प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म और ई-पाठशाला का इस्तेमाल कर छात्रों को पढ़ाने का काम किया जाएगा।
- 12 और चैनल शुरू किए जाएंगे।
- पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा के लिए एक-एक चैनल होगा।
- इन चैनलों से सुबह आठ बजे से दो बजे या शाम सात बजे से रात एक बजे तक प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा स्काईप के सहारे छात्रों के साथ लाइव संवाद भी होंगे।
- इसके साथ ही टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन, जिओ एप्प के जरिए इनका प्रसारण किया जाएगा।

दिव्यांग बच्चों के लिए भी होगी विशेष सुविधा

सीतारमण ने बताया कि इससे देश के 25 करोड़ स्कूली बच्चों को ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षा मिलेगी। नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चों के लिए भी ऑडियो तथा संकेत भाषा में शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा शुरू की जाएगी। वित मंत्री ने बताया कि दीक्षा प्लेटफार्म पर 24 मॉर्च से अब तक 6 करोड़ हिट्स हो चुके है तथा 200 नई ई-बुक भी डाले गए हैं। स्वयं प्रभा चैनल से हर दिन चार घंटे का प्रसारण होगा। स्वयं प्लेटफार्म पर 16 मॉर्च से अब तक 90 हज़ार छात्रों ने दाखिला लिया है।

सीटू का 22 मई को देशव्यापी प्रदर्शन

हैदराबाद। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन (सीटीयू) ने केंद्र सरकार के श्रम कानूनों में बदलाव के प्रयासों के विरोध में 22 मई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव सी वेंकटाचलम ने सीटीयू की ओर से जारी संयुक्त वक्तव्य के हवाले से रविवार को यूनियनों और सदस्यों को लिखे परिपत्र में यह जानकारी दी। सीटीयू की गुरुवार को एक बैठक में पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान कामकाजी लोगों के समक्ष दुरुह स्थिति पर चर्चा की गयी और इस चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त रूप से कदम उठाने का निर्णय लिया गया। वेंकटाचलम ने कहा कि कोरोना वायरस की महामारी की आड़ में सरकार उन श्रमजीवी वर्ग और आम आदमी के हितों के खिलाफकई फैसले लेते जा रही है , जो लॉकडाउन के कारण पहले ही गहरे संकट और दुख में हैं।

कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो न हो, अमेरिका फिर से खुलेगा

उन्होंने घोषणा की कि साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन तैयार करना उनका उद्देश्य है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लोग अपने जीवन में सामान्य रूप से वापस लौटना शुरू करें

वॉशिंगटन ए.। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'कोरोना की वैक्सीन तैयार हो या न हो', अमेरिका फिर से खुलेगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना उनका उद्देश्य है। बीबीसी ने अपनी शनिवार की रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने वैक्सीन प्रॉजेक्ट 'ऑपरेशन वॉर्प स्पीड' की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के पहले परमाणु हथियारों को बनाने के प्रयासों से की।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन के बिना भी अमेरिकियों को चाहिए कि वह अपने जीवन में सामान्य रूप से वापस लौटना शुरू करें। कई विशेषज्ञों को इस बात पर संदेह है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को एक साल की अवधि के भीतर तैयार किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस के रोज गार्डन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'परियोजना 14 वैक्सीन कैंडिडेट पर शोध (रिसर्च) और अनुमोदन (अप्रूवल) के साथ शुरू होगी।'

'वैक्सीन को खोजने के लिए साझेदारी हो'

उन्होंने एक वैक्सीन को खोजने और इसे वितरित करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी की बात कही और ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए सेना के एक जनरल और एक पूर्व हेल्थकेयर एग्जीक्यूटिव का नाम बताया। पहले फार्मास्युटिकल दिग्गज ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में वैक्सीन डिवीजन का नेतृत्व करने चुके मोनसैफसलोई इस मिशन की अगुवाई करेंगे, जबकि अमेरिकी सेना के लिए वितरण की देखरेख करने वाले जनरल गुस्ताव पर्ना चीफऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के बाद मोनसैफसलोई ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि 2020 तक वैक्सीन की कुछ हजार मिलियन खुराकों का वितरण कर दिया जाएगा। बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अभी तक 46 लाख 60 हजार से ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से लगभग तीन लाख 10 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों का आंकड़ा 3 लाख 9 हजार से ज्यादा हो चुका है। इस वायरस से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है, जहां 88 हजार 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है।

ऑनलाइन मनोरंजन में अधिक समय बिता रहे देश के युवा : सर्वे

नई दिल्ली ए.। कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान देश में 25 साल से कम उम्र के लोग और 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोग टीवी कार्यक्रम, फिल्में देखने, गेम खेलने या अन्य ऑनलाइन मनोरंजन में अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। यह बात आईएएनएस-सीवोटर सर्वेक्षण में सामने आई है। सवेक्षण के अनुसार, लगभग 61.1 प्रतिशत फ्रेशर्स ऑनलाइन मनोरंजन में समय बिताते नजर आ रहे हैं, जबकि इससे अगली आयु वर्ग की श्रेणी के 50 प्रतिशत युवाओं का कहना है कि वे अपना अधिकांश समय टीवी या फिल्में देखने में बिता रहे हैं। आय के संदर्भ में देखा जाए तो मध्यम आय वर्ग में 55.6 प्रतिशत लोग अपना अधिकांश समय ऑनलाइन मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं, जबकि निम्न आय वर्ग में 53.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे ऑनलाइन मनोरंजन पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि निम्न आय वाले लोगों को इस संकट की घड़ी में आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है। इस श्रेणी के 39.6 प्रतिशत लोग अधिक समय टीवी या फिल्में देखने में बिता रहे हैं। क्षेत्रीय संदर्भ में देखा जाए तो पूर्व, उत्तर और पश्चिम भारत में लगभग 50 प्रतिशत लोग अधिक समय टीवी या फिल्में देखने में बिता रहे हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में 34.2 प्रतिशत लोग ऐसा कर रहे हैं। वहीं अगर शिक्षा के स्तर को देखते हुए लोगों की दिलचस्पी पर गौर किया जाए तो कम शिक्षित समूहों में आने वाले 43.3 प्रतिशत लोग अधिक समय टीवी देखने में बिता रहे हैं, जबकि मध्यम और उच्च शिक्षित 50 प्रतिशत से अधिक लोग ऑनलाइन मनोरंजन करते हुए अपना समय बिता रहे हैं। सामाजिक या समुदाय के तौर पर देखा जाए तो 70.3 प्रतिशत ईसाई सबसे अधिक ऑनलाइन मनोरंजन करते हुए समय बिता रहे हैं।

जबकि केवल 37.4 प्रतिशत सिख ऐसा कर रहे

प्रवासी मजदूरों ने मथुरा-आगरा हाईवे किया जाम

सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप

मथुरा ए.। लॉकडाउन के कारण शहरों से पलायन कर पैदल ही अपने मूल गृह राज्यों की ओर जाने को मजबूर उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर रविवार को राज्य सरकार की अनदेखी ने नाराज होकर सड़क पर उतर आए और यातायात बाधित कर अपने गुस्से का इजहार किया।

मजदूरों के लिए सरकारों की ओर से पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने से नाराज सैकड़ों प्रवासी मजदूरों ने रविवार को मथुरा जिले के अंतर्गत आने वाले रायपुरा जाट क्षेत्र में मथुरा-आगरा राजमार्ग को रोक दिया। इन प्रवासी मजदूरों की मांग है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनके घरों तक भेजने के लिए सरकार द्वारा व्यवस्था की जाए।

गरीबों के लिए सील की यूपी सीमाएं, घर कैसे पहुंचेंगे श्रमिक : अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर पैदल या निजी वाहनों से अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोकने के लिये सीमाएं सील करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना सड़क के श्रमिक अपने घर कैसे पहुंचेंगे। अखिलेश ने रविवार को ट्वीट किया जिस प्रदेश ने देश को महामहिम दिए, प्रधान जी दिए, उस उत्तर प्रदेश ने अपनी सीमाओं को ग़रीबों के लिए सील कर दिया है। बिना सड़क, प्रवासी मज़दूर भला कैसे बिहार, ओडिशा, झारखंड, बंगाल एवं पूर्वोत्तर जाएंगे। ये हवा-हवाई सरकार कोई हवाई मार्ग ही बता दे।

यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोविड-19 के मरीज और मौत दोनों का आंकड़ा

यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या और इससे मरने वालों का आंकड़ा दोनों ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बीमी से ठीक होने वालों की संख्या भी औसत से ज्यादा है। बावजूद इसके अधिकारी इस बात को लेकर परेशान है कि जिन शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसे कैसे रोका जाए। यही कारण है कि मेरठ में सप्ताह में दो दिन पूरी तरह से लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। आगरा में स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है। यहां संक्रमितों की संख्या ८०० से ज्यादा हो गई है।

एक दिन में मरीजों के मिलने का टूटा रिकार्ड

प्रदेश में 16 मई को अब तक सबसे अधिक मरीज मिले हैं। शनिवार को आई कोरोना वायरस की रिपोर्ट के अनुसार 203 मरीजों में वायरस मिलने की पुष्टि हुई है शनिवार को नौ कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 104 मौतें हो चुकी हैं। मेरठ में कोरोना का कोहराम चरम पर है। शनिवार को आगरा के एक और मेरठ के दो मरीजों ने मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इनमें शामिल एक महिला मरीज की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं अन्य दो पहले से संक्रमित थे। मेरठ में कोरोना से मौत का आंकड़ा 19 हो गया है। वहीं, एक पुलिसकर्मी, एक आशा कार्यकत्री सहित आठ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह मेरठ में कुल संक्रमितों की संख्या 320 हो गई है। उधर, सहारनपुर में मध्य प्रदेश से आए 10 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सहारनपुर में अब कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 203 हो गई है।

केंद्र ने किया आगाह, मेरठ की स्थिति खराब

कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने मेरठ के प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को आगाह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने मेरठ सहित देश के 30 से अधिक महानगरों में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने मेरठ को लेकर कहा कि मेरठ की स्थिति चिंताजनक है। यदि सख्त कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो 15 दिनों में केस दोगुने हो जाएंगे।

भारत के विरोध के बाद भी गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने का दिया आदेश

इस्लामाबाद ए.। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन और चुनाव कराने के लिए आदेश जारी किया है। इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध किया है। राष्ट्रपति कार्यालय से यह आदेश तब जारी किया गया है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की मंजूरी दे दी थी। गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कई विषयों पर कानून बनाने के साथ ही प्रशासनिक बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की मंजूरी दिए जाने के बाद भारत ने इस्लामाबाद के समक्ष उसके 'अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में' स्थिति में बदलाव लाने के उसके प्रयासों के लिए कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को डेमार्श (आपत्ति पत्र) जारी कर अदालत के आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और साफ तौर पर यह कहा था कि गिलगित-बाल्टिस्तान के इलाकों समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ''गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव एवं कार्यवाहक संशोधन आदेश जारी किया। गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 24 जून को पूरा होगा।

राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार बनाने के लिए कानूनों में संशोधन आवश्यक था। डॉन अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गिलगित-बाल्टिस्तान इकाई के अध्यक्ष सैयद जफर शाह ने कहा कि क्षेत्र में कार्यवाहक सरकार बनाने का कोई प्रावधान नहीं था और राष्ट्रपति के आदेश के बाद इस मुश्किल को हटा दिया गया है।

चंद दिनों में भारत में दो बार घुसे चीनी हेलिकॉप्टर

नई दिल्ली ए.। पिछले दिनों भारत और चीन की सेना में झड़प हुए थी और अब लाहौल-स्पीति जिले के एसपी राजेश धर्मानी ने जो जानकारी दी है, उससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को चीनी हेलिकॉप्टर लाहौल स्पीति जिले के संधो क्षेत्र में करीब 12-15 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे। इसके बाद 20 अप्रैल को दोबारा चीनी हेलिकॉप्टरों ने उसी इलाके में फिर घुसपैठ की। उन्होंने बताया कि सीआईडी और अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपनी रिपोर्ट संबंधित अथॉरिटीज़ को सौंप दी है। लद्दाख के पेंगोंग सो सेक्टर में तीन स्थानों पर दोनों पक्षों के 250 से अधिक सैनिकों के बीच 5 और 6 मई को हिंसक झड़प हुई थी। दोनों तरफ से डंडे चले थे और पथराव हुआ था। सूत्रों के मुताबिक इन झड़पों में कुछ अधिकारी और कई सैनिक घायल हुए थे। ये घटना लाहौल स्पीति के कौरिक इलाके की है, जो एलएसी का आखिरी गांव है। यहां पहले भी चीनी सेना की गतिविधियां देखी जा चुकी हैं। अगस्त 2017 में भारत-चीन-भूटान की सीमा पर डोकलाम में सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं। उस दौरान स्थानीय निवासियों ने कहा था कि चीनी सेना एलएसी के पास निर्माण कार्य शुरू कर रही है, जिसके बाद हेलिकॉप्टर की आवाजाही बढ़ गई है।

क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत आमने-सामने

मुंबई ए.। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र में क्वारंटाइन सेंटर को लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत आमने-सामने आ गए हैं। शिव सेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने वानखेड़े स्टेडियम के कुछ परिसरों को कोविड-19 क्वारंटाइन सेंटर में बदलने के लिए अपने कब्जे में लेने के मुंबई नगर निकाय के कदम का रविवार को स्वागत किया और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में भी इसी प्रकार का केंद्र बनाए जाने का सुझाव दिया। हालांकि, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एवं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने संजय राउत के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि स्टेडियमों के मैदान की जमीन मिट्टी की है और मानसून में वे इस्तेमाल करने लायक नहीं होंगे।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को शुक्रवार को निर्देश दिया था कि वह दक्षिण मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम के कुछ परिसरों को उसे सौंपे, ताकि वहां कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र बनाए जा सकें। संजय राउत ने बीएमसी के इस कदम का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, 'वानखेड़े स्टेडियम को अपने हाथ में लेकर क्वारंटाइन केंद्र बनाने का फैसला अच्छा है। उद्धव ठाकरे कार्यालय को मेरा सुझाव है कि क्यों न ब्रेबोर्न स्टेडियम का इस्तेमाल भी इस काम के लिए किया जाए? इसमें आवश्यक सुविधाएं हैं।' संजय राउत ने इस ट्वीट में आदित्य और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी टैग किया।

हालांकि संजय राउत के सुझाव को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने ठुकराते हुए ट्वीट किया, 'संजय जी, हम स्टेडियमों या खेल के मैदानों को नहीं ले सकते क्योंकि उनकी मिट्टी की जमीन होती है और वे मानसून में इस्तेमाल करने योग्य नहीं होंगे। ठोस/कंकरीट की जमीन वाला खुला स्थान ही इस्तेमाल के लायक होगा।' उन्होंने कहा, 'यदि मानसून आने वाला नहीं होता, तो ये बहुत उपयोगी होते।'

आठ करोड़ से अधिक मजदूरों को मिलेगा मुफ्त अनाज : पासवान

नई दिल्ली ए.। कोरोना महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने फिलहाल आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना किसी राशनकार्ड के दो माह तक मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है। पर आने वाले वक्त में सरकार इन मजदूरों तक लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें कल्याणकारी योजना में शामिल कर सकती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि यह राहत अभी दो माह के लिए है, कोराना की क्या स्थिति रहती है, उस बारे में तब निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों को अनाज का आवंटन कर दिया है। प्रवासी मजदूरों की आवाजाही पर निगरानी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड शुरू

उन्होंने कहा कि यह योजना मई और जून के लिए है। ऐसे में राज्यों को राशन वितरित करने के बाद 15 जुलाई तक सभी का नाम भेज देना चाहिए। किसी राज्य में इसके बावजूद भी लोग बच जाते हैं, तो राज्य के आग्रह पर विचार करेंगे। हमारी कोशिश है कि हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। रामविलास पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में 81 करोड़ लोग आते हैं। आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या 89 करोड़ होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके बाद कोई व्यक्ति लाभ के दायरे से बाहर नहीं रहेगा, पर इसके बावजूद भी राज्य सरकार और मांग करती है, तो हम उस पर संवेदनशीलता से विचार करने के लिए

पश्चिम बंगाल में 400 नर्सों ने दिया इस्तीफा

नयी दिल्ली /कोलकाता । देश में कोरोना वायसर (कोविड-19) महामारी की चुनौती के बीच पश्चिम बंगाल के अस्पतालों की 400 नर्सें इस्तीफा देकर अपने गृह राज्यों को लौट गई है। यहां रविवार को प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार शनिवार को मणिपुर की 185 नर्सें अपने गृह प्रदेश लौट गई जबकि ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की 186 नर्सें अपने राज्यों को चली गई है। ये सभी नर्सें कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न निजी अस्पतालों में सेवाएं दे रही थीं।

नर्सो के सामूहिक इस्तीफे के वास्तविक कारणों को अभी खुलासा नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। राज्य में कोरोना वायरस से अब तक 232 लोगों की मौत हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या के मामले में 'विसंगति' को देखते हुए 12 मई को राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सचिव विवेक कुमार को हटा दिया था। राज्य सरकार ने श्री कुमार को हटाने को 'नियमित स्थानांतरण' बताया था। इस कदम को राजनीतिक मायनों में देखा गया क्योंकि राज्य द्वारा प्रदान की गई कोविड 19 के मौत के आंकड़ों की केंद्र सरकार ने गणना की थी।

राज्य सरकार ने मौतों को 'कोविड से मौत' और 'कोविड के साथ अन्य बीमारियों से जुड़ी मौत' के रुप में वर्गीकृत किया था जबकि केंद्र के पास ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं था और उसने कोविड के पॉजिटिव मरीजों के मौत के सभी मामलों की रिपोर्ट दी। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल से नर्सो का सामूहिक इस्तीफा राज्य में स्थिति को 'जटिल' बनाएगा।

भुखमरी से बचने को दिल्ली की 60% से अधिक सेक्स वर्कर अपने घरों को लौटीं

दिल्ली में 5000 रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स

नई दिल्ली ए.। दिल्ली की कई सेक्स वर्कर कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण आजीविका के साधन खत्म होने के कारण भुखमरी की कगार पर आ गईं और अंततः उनमें से 60 फीसदी से अधिक अपने गृह राज्यों को लौट गईं। भयावह बीमारी के डर से इन सेक्स वर्कर्स को अब ग्राहक नहीं मिल रहे जिसका असर इनकी आमदनी पर पड़ रहा है। देशभर के सेक्स वर्कर्स के लिए कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर काम करने वाले समूह ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफसेक्स वर्कर्स की अध्यक्ष कुसुम ने कहा कि दिल्ली की 60 फीसदी सेक्स वर्कर्स अपने गृह राज्यों के लिए निकल चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में रजिस्टर्ड सेक्स वर्कर्स की संख्या कुल पांच हजार है और गृह राज्यों को लौटने वाली सेक्स वर्कर्स की संख्या तीन हजार है। उन्होंने कहा कि खाने और दवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कई हफ्तों के संघर्ष के बाद इन सेक्स वर्कर्स को आखिरकार दिल्ली छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक सेक्स वर्कर ने बताया कि आठ साल दिल्ली में रहने के बाद आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश में अपने गांव को लौट पड़ा। युवती ने कहा कि मैं यूपी के अपने घर से 18 साल की उम्र में भाग गई थी। मैं अभिनेत्री बनना चाहती थी, लेकिन बाद में अपना पेट पालने के लिए इस धंधे में आ गई।

न्यूज़ गैलरी

साधारण बुखार के मरीज को कोविड सेंटर में भर्ती करने का फैसला गलत- भूपेन्द्र गुप्ता

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार के उस फैसले की आलोचना की है जिसमें यह बताया गया है कि कोबिड के डेडीकेटेड केयर सेंटर्स पर मरीज नहीं पहुंचते हैं एवं वे ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जब चीजें नियंत्रण में नहीं रह जाती हैं।गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जिन 21 तरह के लक्षण में से कोई भी लक्षण मिलने पर तत्काल डेडीकेटेड कोरोना केयर सेंटर पर भर्ती कराने हेतु कलेक्टरों को निर्देशित किया है जिससे कोरोना का संक्रमण और भी अधिक फैलने का खतरा बढ़ सकता है। गुप्ता ने कहा कि डेडीकेटेड 440 कोरोना केयर सेंटर पर ना तो उतनी सुविधाएं उपलब्ध है ना ही सैनिटाइजेशन की अगर इन सेंटर्स पर पूर्व से ही कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती होगा तथा साधारण बुखार के लक्षण वाले मरीज को भी वहीं भर्ती कर दिया जाएगा तो संभावित संक्रमण के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? गुप्ता ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताते हुए शासन से इस पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु दिशा-निर्देश

भोपाल। देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों के वर्ष 2020-21 के लिये अनुज्ञप्ति द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन लॉकडाउन की घोषित अवधि के उपरांत ही किया जा सकेगा। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सभी कलेक्टर को लिखा है कि नवीन लाइसेंस जारी करने के लिये आनुपातिक आकलित वार्षिक मूल्य के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति राशि 20 प्रतिशत बैंक गारंटी/सावधि जमा या नगद राशि लाइसेंस जारी करने के दिनांक से 7 दिवस में अगली 20 प्रतिशत राशि लाइसेंस जारी करने की दिनांक से आगामी 15 दिवस एवं शेष 60 प्रतिशत आगामी 45 दिवस की अवधि में अनिवार्य जमा कराई जाये। साथ में प्रतिभूत राशि लाइसेंस जारी करने की दिनांक से 45 दिवस के अन्तर्गत अनिवार्यत~ प्राप्त की जाये। कोविड-19 की रोकथाम के लिये विभिन्न जिलों में लॉकडाउन अवधि प्रभावी है।अत~ ऐसी दुकानों के लिये बैंक गारंटी जमा करने के लिये लाइसेंस जारी होने के बाद जिस दिनांक से मदिरा दुकान को खोले जाने की अनुमति हो उस दिनांक से आगामी 7 दिवस एवं अग्रेत्तर दिवसों की गणना की जाये। यदि किसी समूह की कुछ दुकानें खुल गई हो, तो उस समूह हेतु बैंक गारंटी जमा करने की बाध्यता उन खुली हुई दुकानों के लिये ही प्रभावी होंगी। समूह की अन्य शेष दुकानें खुलने की विधिवत अनुमति प्राप्त होने पर लाइसेंसी को बैंक गारंटी भी नियमानुसार देनी होगी। अन्यथा समूह की समस्त दुकानों के लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे। शेष व्यवस्था पुर्वानुसार होगी। राज्य शासन ने उक्त संशोधित व्यवस्था मूल परिपत्र 31 मार्च 2020 से प्रभावी किया है।

मध्यप्रदेश के हालात बेहद चिंताजनक , संक्रमण व मौतों के आंकड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं : कमलनाथ

कमलनाथ का शिवराज सरकार पर तीखा प्रहार

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज कोरोना को लेकर लॉकडाउन का तीसरा चरण समाप्त हो रहा है।इन तीन चरणों की समाप्ति के बाद भी मध्य प्रदेश की स्थिति कोरोना को लेकर बेहद चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण व इससे हो रही मौतों के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नाथ ने बताया कि प्रदेश में लॉकडाउन के पहले दिन 24 मार्च तक कोरोना संक्रमण के मात्र 4 मरीज थे और आज बात करें तो लॉक डाउन 3 की समाप्ति पर प्रदेश में कोरोना संक्रमितो का आंकड़ा बढ़कर 5000 के करीब पहुंच चुका है ,250 के करीब मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है ,प्रदेश के 45 से अधिक जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं , 100 से अधिक गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।अब यह महामारी शहरों से गांव की और भी निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश का इंदौर देश का 7 वा और भोपाल देश का 11 वां हॉटस्पॉट बन चुका है।प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमितो का आंकड़ा एक हजार को पार कर चुका है ,वहीं 38 मौतें अभी तक हो चुकी है।वही बात करें प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की तो वहां कोरमा संक्रमितो का आंकड़ा 2500 के करीब पहुँच चुका है और मौतों का आंकड़ा 100 पर पहुंच चुका है।यह सारे आंकड़े बेहद चिंताजनक है।जिस हिसाब से प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ता जा रहा है ,उस हिसाब से आज भी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने की आवश्यकता है।आज भी पीपीई किट से लेकर मास्क व अन्य सुरक्षा संसाधनों के अभाव में कोरोना वारियर्स प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं।जिस हिसाब से कोरोना के संक्रमण के आंकड़े प्रतिदिन बढ़ रहे हैं , उस हिसाब से प्रदेश में आज भी वेंटिलेटर से लेकर अन्य आवश्यक मेडिकल उपकरणो का अभाव है।आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 75000 लोगों पर एक वेंटीलेटर है और 47000 लोगों पर एक आईसीयू बेड की उपलब्धता है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर निजी अस्पतालों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है , वही करीब 10 जिलों में कुल वेंटिलेटर की संख्या 5 भी नहीं है। प्रदेश के भोपाल-इंदौर - जबलपुर जैसे शहरों में भी इस महामारी के बढ़ते आँकड़ो को देखते हुए आवश्यकता अनुसार इनकी कमी है।आज भी निजी अस्पतालों में आम मरीजों को इलाज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है , वही कोरोना मरीजों से भी भारी भरकम बिल वसूले जा रहे हैं।इन पर सरकार का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है।आज भी प्रदेश में लोगों को दूध-दवाई व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ,वही शराब की आपूर्ति सरकार द्वारा करा दी गई है।मंदिर -मस्जिद -गुरुद्वारे व अन्य सभी धार्मिक स्थल बंद है ,वहीं शराब की दुकानें चालू है। आज भी प्रदेश वापसी कर रहा मज़दूर बेहद परेशानियो का सामना कर रहा है।आज भी प्रदेश के सभी मार्ग व सीमाएँ इन मज़दूरों से भरी पड़ी है। साधन के अभाव में हज़ारों ग़रीब-बेबस-लाचार मज़दूर भूखे प्यासे , भीषण गर्मी में नंगे पैर , पैदल ही अपने घर की और जा रहे है।सरकार के सारे दावे हवा-हवाई साबित हो रहे है।सरकार की बसे व साधन कही नज़र नहीं आ रहे है।इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। नाथ ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के साथ ही चौथे चरण की शुरुआत में जनता को राहत प्रदान की जाए ,रेड जोन छोड़कर अन्य इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।क्रमबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो।संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाकर कार्य करें।

मप्र: लॉकडाउन फेज-3 का 14वां दिन

मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा

सरकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर जोर रहेगा, रेड जोन में राहतें मिलने की उम्मीद नहीं

फेज-4 में अब राज्य की कुल संक्रमित केस की 80 फीसदी संख्या वाले जिले को रेड जोन के दायरे में रखा जाएगा

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस बारे में गाइड लाइन जारी होना बाकी है। राज्य के रेड जोन और कंटेनमेंट जोन के बारे में कुछ शर्तो के साथ गाइड लाइन जारी होने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों में पूर्व की तरह ही सख्ती बरती जाने की संभावना है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का स्वरूप निर्भर करेगा। प्रदेश के इंदौर, राजधानी भोपाल और उज्जैन जैसे शहरों में पूर्व की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेंगे इतना तय है। रविवार शाम देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है उसके अनुसार 18 मई से शुरू होने वाले फेज 4 में कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में ऑनलाइन क्लासेस के लिए 33 फीसदी स्टाफ को बुलाया जा सकेगा। छात्रों को आने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट दफ्तर 33 फीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही दफ्तर खोलने की अनुमति रहेगी। रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे, रजिस्ट्री हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब दुकानें खोलने की भी तैयारी है। लेकिन इसमें अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। अभी यह सुझाव डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की ओर से दिया गया है। भोपाल में रविवार दोपहर 38 नए संक्रमित मिले। इनमें 10 जहांगीराबाद इलाके के हैं। राजधानी में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1057 पर पहुंच गया है। अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर ये है कि रविवार को 27 लोग स्वस्थ होने पर घर भेजे गए। ये सभी लोग यहां चिरायु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे। अब तक 660 मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं। यहां एक्टिव मरीज 373 हैं। इधर, कुवैत से लौटे 6 अन्य प्रदेशों के लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटव आई है। इससे पहले शनिवार तक कुवैत से लौटे 19 लोग पॉजिटिव पाए गए थे।

25 जून तक एमपी में आएगा मानसून, सामान्य बारिश का पूर्वानुमान

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल 25 जून तक मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। 28 से 30 जून के बीच ग्वालियर चंबल संभाग में मानसून का प्रवेश होने की संभावना है। हालांकि, केरल तट पर मानसून के पहुंचने में देरी का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले बताया था कि केरल तट पर 1 जून को मानसून प्रवेश करेगा, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4-5 जून कर दिया गया है।

देश में मानसून का सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक रहता है, लेकिन देरी के चलते मौसम विभाग ने मानसून चक्र की तारीखों में बदलाव किया है। मुंबई, पुणे और नागपुर के साथ एमपी में भी मानसीन की तारीखें बदली हैं। 15 अप्रैल को विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में 31 मई से 1 जून के बीच केरल तय पर मानसून के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन इसमें 4 दिन की देरी हो रही है। इसीलिए, ग्वालियर चंबल संभाग में भी इसकी तारीखें आगे बढ़ाई गई हैं। भोपाल में भी मानसून के आने की तारीख 15 जून है, लेकिन इस बार इसके 22 जून तक आने की उम्मीद है। प्रदेश में इस साल मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। अधिकतर इलाकों में 96 से 104 प्रतिशत तक बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर इससे ज्यादा बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 96 से 104 प्रतिशत तक बारिश को सामान्य माना जाता है।

भ्रमण

मंत्री डॉ. मिश्रा ने दतिया में राहत सामग्री और मास्क वितरित किये

भोपाल। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया शहर और आसपास के गांवों का भ्रमण कर ग्रामीणों को राहत सामग्री और मास्क का वितरण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव की समझाईश देते हुए सेनिटाईजेशन का महत्व समझाया और लोगों के हाथ भी सैनिटाईज किए। डॉ. मिश्रा ने आज ग्राम चिरोला, करारी-खुर्द, पट्टापुरा और दतिया शहर के गोविंदगंज में लोगों से मुलाकात कर उनका हाल-चाल जाना। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि कोरोना संकट की इस घड़ी में आमजन को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। लॉक डाउन और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और सुरक्षित रहें।

अर्थ चक्र में व्यवधान ;डीए व एरियर रोकना नहीं है समाधान

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। विश्व व्यापी कोविड-19 महामारी संकट के दौर में अर्थव्यवस्था की गाड़ी को भारत सरकार ने बीस लाख करोड़ के पैकेज से पटरी पर लाने का ऐलान किया है। इसे विगत चार दिनों से केंद्रीय वित्त मंत्री/वित्त राज्यमंत्री ÷श्रीमती निर्मला सीतारमण÷ व ÷श्रीमान पीयुष गोयल÷ लगातार चरणबद्ध तरीके से विस्तार से बता रहे हैं। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री प्रमोद तिवारी एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने संयुक्त प्रेस नोट में बताया है कि इसके उलट मप्र में पहले केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले जुलाई 2019 से मिलने वाले 5त्नडीए व अब सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी अंतिम किश्त का भुगतान ÷बमुश्किल आदेश÷ होने के बाद स्थगित कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को इनका पहले ही भुगतान हो चुका है। इस निर्णय से अर्थ तंत्र को पंगु बनाने में इजाफा होगा। विगत मार्च माह में लाखों मध्यम आय वर्ग कर्मचारियों ने आयकर व वृत्ति कर का भुगतान किया है। पहले से आर्थिक परेशानी झेलते ÷डीए व सातवें वेतनमान के एरियर÷ की तृतीय व अंतिम किश्त रोककर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति कमजोर करने के परिणाम स्वरूप ÷क्रय शक्ति÷ पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। सरकार का यह कदम हर दृष्टि से नुकसान दायक सिध्द होगा। इससे एक तरफ कर्मचारियों में आर्थिक बदहाली से भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त हैं, दुसरी ओर क्रय शक्ति कमजोर होने से बाजार की सेहत भी प्रभावित होगी। इसका सीधा असर बेरोजगारी में वृद्धि व राजस्व में कमी के रूप में तो सामने आयेगा वहीं केंद्र के प्रयासों में भी व्यवधान उत्पन्न करेगा। ÷मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ÷ प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान शिवराजसिंह जी चौहान से निवेदन करता है ।

कांग्रेस के जनसेवा केन्द्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। लॉक डाउन के चलते महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात और मध्यप्रदेश के पडोसी राज्यों से हजारों किलोमीटर पैदल चलकर, साईकिल, कार, मोटर साईकिल, और ट्रकों से अपने घर लौट रहे श्रमिकों को कांग्रेस जनसेवा केन्द्र के जरिए सूखी सेवनिया चौराहे पर भरपूर मदद कर रही है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जनसेवा केन्द्र पहुंचे और उन्होने घर लौट रहे मजदूरों को भोजन के पैकेट, पानी की बोतल, बिस्किट, नमकीन, हैंड सैनेटाइजर पाउच, ओआरएस, वितरित कर मजदूरों की मदद की वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने नंगे पैर पैदल चल रहे मजदूरों को चरण पादुकाएं भी पहनाई। उन्होने बाहर से आ रहे मजदूरों से कोरोना काल में आर रही दिक्कतों, सरकार से मिलने वाली मदद और खाने पीने के इंतजाम पर भी बात कि। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार कहती है मजदूरों को मुफ्त ले जाया जायेगा लेकिन मजदूरों से घर वापसी के नाम पर ट्रक, आटो, गाडी में तीन हजार से चार हजार रुपये प्रति मजदूर वसूला जा रहा है लेकिन सरकार शांत है राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को आगे आना चाहिए, 20 लाख करोड के पैकेज में इन मजदूरों को क्या मिला है क्या इनके आने जाने का खर्चा इनकों मिलेगा या इनका खर्चा रियमेबर्स होगा, कोरोना संकट के समय जो योजना बनना चाहिए थी वह नही बनी। उन्होने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जनसेवा केन्द्र शुरु किया है उससे लोगों की मदद की जा रही है। उन्होने सुझाव दिया कि पूरा जिला रेड जोन बनाने की जरूरत नही है जिले के बजाये थाने स्तर पर एरिया को बांटा जाये, जहां कोरोना पेशेंट मिले उस थाने के एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया जाये और जिस मोहल्ले में 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले उसे हॉट स्पाट घोषित कर दिया जायें, वहां आने जाने की किसी को अनुमति नही दी जाये। बाकी एरिया को कंट्रोल तरीके से खोला जाना चाहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चौथे लॉक डाउन शुरु होने पर कहा कि तीसरे लॉक डाउन के आखिरी दिन 5 हजार केस आये है और 120 लोगों की जान गई है

पॉजिटिव केस में बागसेवनियां टॉप पांच में, होशंगाबाद रोड की कॉलोनियों के लिए अलार्म, जाटखेड़ी तक पहुंचा कारोना

छतरपुर, झांसी, बुंदेलखंड, बड़वानी, झाबुआ और अन्य जिलों से आए मजदूरों ने बसाई थी बस्ती

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। सुबह मेहनतकर शाम को दो जून रोटी कमाने वाले मजदूरों को कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ा। सरकार की तरफ से दी गई मुफ्त राशन की व्यवस्था पर दूसरों ने डाका डाल दिया। मजबूरी और हालात ने इस कदर बेबस कर दिया कि उन्हें अपने सपनों के आशियाने में ताले डालकर अपने गांव ही जाना पड़ा। कोलार बंजारी में पूरी बस्ती दिहाड़ी मजदूरों और घरों में काम करने वालों की बसी है। इसमें से अस्सी फीसदी घरों में आज ताले डले हैं। घर अंदर से खाली हैं, अगर कुछ है तो सोने की कुछ चारपाई ही झुग्गियों में रखी हैं। बाकी मजदूर अपना सामान समेट कर ले गए। उनके जाने के बाद यहां की गलियां सूनी पड़ी हैं। कल तक यहां हजारों मजदूरों की चहल पहल होती थी। गोविंदपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया में गौतम नगर बस्ती में झुग्गी रहने वाले मजदूर अपने घर आष्टा चले गए। यहां रहने वाले मजदूर इडस्ट्री में काम करते थे और अपना गुजारा करते थे। लेकिन लंबे समय से बंद पड़े इंडस्ट्रीयल एरिया के चलते इन लोगों को खाने के लाले पड़ गए। दो लोग वहीं घूमते मिले उन्होंने अपने राम रमेश और सुखलाल साहू बताया। दोनों का कहना है कि यहां रोजाना काफी चहल पहल रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मजदूर परिवार को लेकर चले गए। अब यहां सन्नाटा पसरा है। श्यामला हिल्स, मांडवा बस्ती और बाणगंगा में भी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर गए। यहां बचे कुछ मजदूरों मे केशव बताते हैं कि घर में खाने को कुछ बचा नहीं है। आस-पास के लोगों से कुछ उम्मीद रहती है। वो भी कब तक खिलाएंगे। सरकारी राशन की दुकान पर राशन मिलता नहीं है। 18 मई से कुछ आस है, नहीं खुलेगा तो ये भी परिवार के साथ अपने गांव चले जाएंगे।

मजदूरों के पीठे सूने, निशातपुरा से मजदूर गायब

शहर में कोलार, बंजारी, दानिश कुंज, दानापानी के पास मीरा नगर बस्ती, अन्ना नगर, हबीबगंज स्टेशन के सामने, मिसरोद, बागसेवनियां, करोद, अशोका गार्डन, टीटी नगर, अयोध्या बायपास, गोविंदपुरा, निशातपुरा, ईटखेड़ी ये ऐसे स्थान हैं जहां सुबह-सुबह मजदूर खड़े मिल जाते थे। लेकिन शहर से दो लाख के आस-पास मजदूर पलायन करने के कारण अब ये पीठे सूने रहते हैं। निशातपुरा में जहां रेलवे का माल लोड अपलोड होता है, सीमेंट की बोरियां उतरती हैं, वहां भी अब मजदूर तलाशे नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति में जिले में 95 फीसदी निमार्ण कार्य बंद हैं, जो काम चल रहे हैं उनमें 30 फीसदी मजदूर ही आ रहे हैं। इसका भी कई जगह विरोध शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गिट्टी कोपरा की खदानें चालू की गई हैं, लेकिन निर्माण कार्य से सप्लाई न होने से यहां काम करने वाले पांच हजार मजदूर एक तरह से बेरोजगार हैं।

संपादकीय

कोरोना के संघ जीना सीखना होगा

वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस से छूटकारा मिलना आसान नहीं है। अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी है और न ही इसके जल्द बनने की दूर-दूर तक कोई संभावना नजर आ रही है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक नहीं लग पाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सहित विश्व के अनेक देश लॉकडाउन का सहारा ले रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन को भी लंबे समय तक लागू नहीं रखा जा सकता। आज नहीं तो कल सभी देशों को लॉकडाउन हटाना ही पड़ेगा। वरना लोग कोरोना से कम और भूख से ज्यादा मर जाएगें। कई देशों में तो लॉकडाउन खत्म करने की मांग को लेकर लोग आंदोलन भी कर रहे है। इधन कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भारत में भी कोरोना सक्रंमित मरीजों की संख्या 90 हजार के पार पहुंच चुकी है और एक दो दिनों के भीतर यह एक लाख के पार भी पहुंच जा सकती है। इसके बावजूद भारत ने लॉकडाउन 4 में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत देने पर सरकार विचार कर रही है। यह जरूरी भी है। यदि सभी आर्थिक गतिविधियां ठप्प रखी गई तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है और देश के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में जबकि कोरोना वायरस से छूटकारा असंभव की हद तक कठिन हो गया है। हमें कोरोना के संघ ही जीना सीखना होगा। आवश्यक सावधानी बरतकर सब को अपने काम पर लगना होगा। लॉकडाउन में भी आवश्यक सेवाओं को जारी रखा गया है और आगे चलकर कुछ गैर जरूरी सेवाओं को भी कड़ी शर्तों के साथ शुरू करने की योजना है। दरअसल इसके अलावा सरकार के पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि अब धीरे-धीरे लॉकडाउन को हटाया जाए ताकि सामान्य कामकाज हो सके। इसके लिए भारत को विदेशों से सीख लेने की जरूरत है। जहां लॉकडाउन को हटाकर आर्थिक गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टिंसिंग का कड़ाई पूर्वक पालन कराया जा रहा है। भारत में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके लिए सख्त नियम और कायदें बनाने होंगे क्योंकि हमारे यहां जाहिलों की कोई नहीं है। जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते रहे है। उन्हीं की वजह से हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला है और इसके और ज्यादा फैलने की आशंका बनी हुई है। अभी भी ऐसे अराजक तत्व कोरोना योद्धाओं के ऊपर हमला करने से बाज नहीं आ रहें है। मुंबई जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज है वहां कल फिर इन जाहिलों ने पुलिस कर्मचारियों पर प्रणाघातक हमला किया है। यही वजह है कि भारत में बार-बार लॉकडाउन बढ़ाना पड़ रहा है। अब चौथी बार लॉकडाउन नए रुप में बढ़ाया जाएगा लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्रि हैंड दें अन्यथा कोरोना वायरस के संक्रमण असंभव हो जाएगा।

प्रतिकूलता से निपटना और उसके आगे देखना ही नेतृत्व होता है

प्रकाश जावड़ेकर

यह संघवाद की वास्तविक भावना के अनुरूप सुधार को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावाए इन सुधारों में से कई बिजली सुधारए व्यापार करने में आसानीए शहरी स्थानीय निकाय सुधारए आदि को सार्वभौमिक रूप से इन्हीं टिप्पणीकारों की मांग थी और वे अब इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। सच्चा नेतृत्व संस्थागत सुधार को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के बारे में होता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व वह है जो न केवल तात्कालिक चुनौती से जूझता है बल्कि देश को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए तैयार करता है। इतिहास ने दिखाया है कि इस तरह के वैश्विक संकट के बाद विश्व व्यवस्था बदल गई है। भारत सौभाग्यशाली है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि पिछले सप्ताह के कार्यों ने दर्शाया है कि वे अवसर को पूरी तरह से समझते हैं।

किसी देश पर कोई संकट आता है तो वह उसके शीर्ष नेतृत्व को एक से अधिक तरीकों से परखता है। सबसे पहले तो जब कोई संकट आता है तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के खतरे को बहुत पहले भांप लेने के साथ-साथ सतर्क निर्णायक कदम उठाने से देश में इस वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद मिली और भारत को कई अन्य देशों से अलग भी खड़ा किया। अब तो प्रधानमंत्री द्वारा की गई देश को महत्वपूर्ण क्षति से बचाने की त्वरित कार्यवाही को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है।

कहा जाता है कि विपत्ति के दौरान ही लोगों का असली चरित्र सामने आता है। यही बात नेतृत्व पर भी समान रूप से लागू होती है। सामान्य काल में नेतृत्व प्रदान करना भले ही चुनौती न हो मगर कठिनाई के समय ही वह बाकी से अलग होकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। दुनिया भर में कोविड.19 महामारी नेतृत्व की परीक्षा ले रही है। इस परीक्षा में भारत और उसके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल वायरस के खिलाफ एक उत्साही लड़ाई कर रहा हैए बल्कि संकट के बाद की कोविड दुनिया को भी देख रहा है और इसके लिए खुद को सावधानीपूर्वक तैयार कर रहा है ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कदम आगे रख सके। आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट आह्वान और उसके बाद पांच दिनों की अवधि में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिन्हें भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा। आसन्न संकट से नहीं घबराने के प्रेरक संदेश के साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने के संदेश ने हर भारतीय को उत्साह से भर दिया है। भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रत्येक क्षेत्र की कहानी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गहन सुधार देखा जा सकता है। भारत के विकास के पहिये गरीबए रेहड़ी थाडी वालों ;स्ट्रीट वेंडर्सद्ध और प्रवासी मजदूरों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से लेकर सभी प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्नए मामूली ऋण लेने वाले मुद्रा लाभार्थियों के लिए ब्याज में छूट से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की सुविधा देनेए मनरेगा आवंटन को बढ़ावा देने से लेकर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को

सशक्त बनाने तक के उपाय कर के आर्थिक पैकेज ने उन लोगों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है जो कोविड.19 के आर्थिक परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत के विकास के वाहनों में से एक है जो विशेष रूप से इस क्षेत्र की रोजगार की गहन प्रकृति के कारण महत्वपूर्ण है। रियायती ब्याज दरों पर इन उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी बिना किसी कोलेटरल के अपने आप दिये जाना इन उद्यमों को एक अतिरिक्त खुराक के रूप में हैं। सूक्ष्मए लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में आमूल.चूल विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कंपनियां अपने विशिष्ट लाभों को खोने के डर से निरुत्साहित न हों। इन उद्यमों के लिए संदेश है .बड़ा सोचो और बढ़ो।

कई कृषि विशेषज्ञों ने हाल के कृषि सुधार उपायों को स्वतंत्रता आंदोलन के समान माना है। अभी की कृषि विपणन मॉडल ऐसा था कि जो उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था जबकि बिचौलियों की पौ बारह थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव से किसानों को अपनी उपज जिसे भी वे चाहें को बेचने की स्वतंत्रता मिली है। ए फार्म.गेट बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश और खेती और उद्योग को एक साथ लाने के लिए दिये गए समर्थन से कृषि को वास्तव में किसानोन्मुख बनाया गया है।

याद रखें कि उपरोक्त दो क्षेत्र . कृषि और सूक्ष्मए लघु व मध्यम उद्यम भारत में दो सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों में व्यापक सुधार देश के लिए बहुत अनुकूल है। दूसरी ओर कोयला खनन रक्षा विमानन और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वभौमिक सुधारों ने सरकार के सुधारवादी रुझान को दर्शाया है। आरबीआई द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए भारी तरलता उपायों और 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज ने भारत के कोविड बाद के विकास की राह प्रशस्त की है। इस तरह के प्रभावशाली कदमों के बावजूदए कुछ नकारात्मकए कुछ टिप्पणीकार वर्ग और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है।

सबसे पहले तो वे दावा करते हैं कि सरकार ने लोगों के हाथों में पैसा नहीं रखा है। शायद इन लोगों की याददाश्त थोड़ी कम है। सरकार द्वारा घोषित सबसे पहला राहत पैकेज गरीबों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज का 1.7 लाख करोड़ रुपये का था। यूपीए युग के विपरीत यह सिर्फ एक घोषणा नहीं रहा। अब तक 39 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 35.000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिल भी चुकी है। इसमें 8 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं जिन्होंने अपने खातों में 2.000 रुपये प्राप्त किए और 20 करोड़ से अधिक जन धन खाताधारी महिलाओं ने सहायता की पहली और दूसरी किस्त प्राप्त की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के तहत कवर किया जाता हैए जिन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जाती है। ये बिना किसी लीकेज के सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं।यह सही तरीके से सही फैसले लेने की बात भी है।

यूपीए की तथाकथित ऋण माफी को हर कोई याद करता है जो किसानों तक किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं पहुंची बल्कि उसने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जबकि यहां मोदी सरकार सीधे लोगों तक पहुंच रही है और जांच परख कर उपाय कर रही है। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3ः से बढ़ाकर 5ः करने वाले राज्यों की उधार सीमा को बढ़ाना भी है। यह राज्यों के लिए अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित करता है। फिर भीए कुछ टिप्पणीकार हैं जो इसे संघीय विरोधी भावना के विरुद्ध बता रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस अतिरिक्त 1.5ः ; अतिरिक्त 0.5ः स्वतः हैद्ध को राज्यों के सुधारों को पूरा करने से जोड़ा है। हमें याद रखना चाहिए कि राज्य पहले से ही अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3ः के हकदार थे और सरकार ने वास्तव में इन सुधारों से अपनी उधार सीमा को बढ़ा दिया है। ***(लेखक केंद्रीय पर्यावरणए वन और जलवायु परिवर्तन सूचना और प्रसारण और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं)***

विचार

साथ-साथ चलेगा कोरोना

लॉकडाउन के तीन चरण पूरे कर लेने के बाद देश इसके चौथे चरण के लिए कमर कस रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तमाम मोर्चों पर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। भारत में संक्रमण का पता लगाने के लिए किए गए टेस्ट्स की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। संसाधनों की सीमा को देखते हुए माना जा रहा था कि यह लक्ष्य मई के अंत तक ही हासिल हो पाएगा। मगर सरकारी और गैर-सरकारी लैब्स में कोरोना वॉरियर्स के दिन-रात लगे रहने का परिणाम है कि यह टारगेट दो सप्ताह पहले ही हासिल कर लिया गया। हमारे यहां कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या अमेरिका और यूरोप से काफी कम है, लेकिन संक्रमण फैलने की गति लगभग वैसी ही है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ भारत की तुलना बात-बात पर होती है, लेकिन महामारी से निपटने के दोनों देशों के तरीके बिल्कुल अलग रहे हैं। चीन में इस वायरस का प्रकोप मुख्यतः उसके एक शहर वूहान तक सीमित रहा मगर भारत में इसकी शुरुआत पूरे देश के पैमाने पर हुई। यूरोपीय देशों में इससे संक्रमित बिना लक्षणों वाले मरीज भारत के अलग-अलग शहरों में तब आए जब वहां भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। भारतीय हवाई अड्डों पर सिर्फ बुखार नापकर उन्हें आगे जाने दिया गया। नतीजा यह कि रोक-छेंक शुरू होने से पहले ही बीमारी देश के हर हिस्से में फैल चुकी थी। याद रहे, शुरू से ही खतरनाक माने जाने के बावजूद इस वायरस को लेकर सरकारों और जनसमूहों का रुख बदलता रहा। हर देश के जिम्मेदार लोग पहले डिनायल मोड में गए। भारत में तो यह वायरस आ ही नहीं आ सकता, आ भी गया तो मई में पारा 40 डिग्री लांघते ही जुकाम के वायरस की तरह टें बोल जाएगा। यह भी कि हमारे देसी नुस्खे इसकी बैंड बजा देने के लिए काफी हैं। जब यह बीमारी इटली में तबाही मचा रही थी, तब भी एक दिन के जनता कर्फ्यू के दौरान लोग इस बात को लेकर आश्वस्त दिखे कि इस मास्टरस्ट्रोक से कोरोना का इंसानी संपर्क टूट जाएगा और उसका खेल खत्म हो जाएगा! ऐसी गलतफहमियां बीमारी के बढ़ाव के साथ ध्वस्त होती गईं। और अब, तमाम देशों द्वारा अपनी सीमाएं सील करने, एक-दूसरे से हवाई संपर्क तोड़ने और तमाम आर्थिक गतिविधियां रोक देने, शारीरिक दूरी और लॉकडाउन का रास्ता अपनाने तथा करोड़ों लोगों को भुखमरी की जद में ला देने का लंबा दौर गुजर जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन बता रहा है कि कोरोना वायरस निकट भविष्य में विदा हो जाने वाली चीज नहीं।

मजदूर, घर वापसी, पलायन, और राहत पैकेज ?

डॉ शिशिर उपाध्याय

आहुति देते समय यदि आप अपने इष्ट देवताओं को याद करते हैं और किसी भी भाषा में याद करते हैं तो इस मजबूरी को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। यदि वे लोग ''अल्लाहाय स्वाहा'' कहेंगे तो वे देवभाषा संस्कृत बोलेंगे और अरबी भाषा में ईश्वर को ही अल्लाह कहेंगे। इसमें गलत क्या है ? महर्षि के सत्यार्थप्रकाश का उर्दू और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो क्या वह पढ़ने लायक नहीं रहा ? जो लोग विदेशियों और विधर्मियों से मंत्रपाठ का दुराग्रह कर रहे हैं, क्या वे उन मंत्रों के अर्थ भी हमें बता सकते हैं ? क्या वे उन मंत्रों का शुद्ध सस्वर-पाठ कर सकते हैं ? वास्तव में डॉ. वैदिकजी ने हवन के नए मार्ग को खोलकर दयानंद के विचार को विश्व-व्यापी रुप दे दिया है। उनके इस मौलिक अवदान के लिए आर्यसमाजियों को उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि स्वयं महर्षि दयानंद ने आर्यसमाज के छठे नियम में कहा है, ''संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है।

प्रधानमंत्री सहायता कोष यानी पीएम केयर्स से एक हजार करोड़ रुपए की मदद मजदूरों को पहुंचाने की घोषणा की गई है। यह रकम स्वतंत्र रूप से सिर्फ शहरों से बेरोजगार होकर अपने गांव पहुंचने वाले मजदूरों के लिए है। निश्चय ही इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मगर यह मदद राज्य सरकारों की मार्फत उन्हें मिलनी है, इसलिए उनकी संजीदगी पर निर्भर है कि वे मजदूरों तक इसका कितना लाभ पहुंचा पाती हैं। पूर्णबंदी के तीसरे चरण में मजदूरों की घरवापसी तेजी से बढ़ी। चिलचिलाती धूप में उन्हें सड़कों पर पैदल, साइकिलों से या फिर ट्रकों वगैरह में छिप कर लौटते देखना एक त्रासद अनुभव है। ऐसे में कुछ राज्य सरकारों ने उनकी वापसी के लिए रेलें चलाने का फैसला किया और धीरे-धीरे विशेष गाड़ियां चलनी शुरू हुई, राज्य सरकारों ने विशेष बस सेवाएं भी शुरू की। मगर बिहार सरकार अब भी इसी पक्ष में है कि जो लोग जहां हैं, वहीं रहें, उन्हें वापस न लौटने दिया जाए। जांच वगैरह के मामले में भी बिहार सरकार की तैयारियों पर अंगुलियां उठ रही हैं। ऐसे में पीएम केयर्स का पैसा वहां किस रूप में और कितना सही हकदारों तक पहुंच पाएगा, कहना मुश्किल है।

इस वक्त राज्य सरकारों के सामने दोहरी चुनौती है कि किस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए और दूसरी तरफ किसी को भूख और बदहाली से न मरने दिया जाए। जिस तादाद में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं, उनसे गांवों में संक्रमण फैलने का खतरा निस्संदेह बढ़ गया है, पर उन्हें बदहाली में बंद करके कहीं और नहीं रखा जा सकता। पीएम केयर्स से मिले पैसे को ईमानदारी से इन मजदूरों की सेहत और पोषण पर खर्च करने के व्यावहारिक कदम उठाने होंगे। अपने घरों को लौट रहे लोगों की पहचान करना मुश्किल काम नहीं है। ग्राम पंचायतों, पटवारी वगैरह को इस काम में लगा कर जल्दी से सूची तैयार कर उन्हें मदद

मुहैया कराने का काम होना चाहिए। बिहार सरकार जैसी निष्क्रियता इन मजदूरों की बदहाली और बढ़ाएगी। इस वक्त अपने गांव लौटे मजदूरों के सामने सबसे विकट समस्या है। एक तरफ तो उनका आमदनी का जरिया खत्म हो गया है और दूसरी तरफ उन्हें उसी ठीये पर पैर जमाने की कोशिश करनी है, जहां की बदहाल स्थितियों से परेशान होकर वे शहरों की तरफ गए थे। शहरों में रहते हुए जो कुछ उन्होंने कमाया था, वह सब कुछ वे गंवा चुके हैं। गांव लौट कर भी उन्हें किस तरह दो जून की रोटी नसीब होगी, इसकी चिंता बनी हुई है। ऐसे में पीएम केयर्स का पैसा अगर सीधे उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तो उनके लिए बड़ी मदद होगी। मगर अभी तक इन मजदूरों की सही पहचान, इनका पंजीकरण आदि नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन्हें मदद पहुंचाने में सरकारों को अड़चन आ सकती है। ऐसे वक्त में राज्य सरकारों की संजीदगी की जरूरत है कि वे कैसे वापस लौटे मजदूरों की दशा सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं।

पूर्णबंदी के समय के अनुभवों से कुछ सबक मिले हैं। राज्य सरकारों ने गरीबों के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया, कुछ नगदी भी उनके खातों में डाली गई, मगर जिन लोगों का पंजीकरण नहीं था, उन तक वह मदद नहीं पहुंच सकी। वे खैरात के भोजन के भरोसे ही जिंदा रहने का प्रयास करते रहे। वही समस्याएं पीएम केयर्स से मिली मदद के आबंटन में भी आ सकती हैं। उधर, मध्य प्रदेश के गुना में 60 से अधिक मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक से विपरीत दिशा से आ रही बस टकरा गई। इनमें सवार आठ मजदूर कभी घर नहीं लौट सकेंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैड़ ये दुर्घटनाएं प्रमाण हैं कि ऐसे समय में भी परिवहन नियमों की पालना नहीं हो रही है। राजमार्गों पर गाड़ियां अंधाधुंध दौड़ने लगी हैं। ठीक इसी प्रकार बिहार में मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही बस से ट्रक भिड़ गया। करीब 30 मजदूर घायल हुए और दो की मौके पर ही मौत हो गई। तीन राज्यों में हुए ये तीन हादसे एक ही तरह की लापरवाही के दुष्परिणाम हैं। जाहिर है, इन मजदूरों के आश्रितों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। ध्यान रहे, ये मजदूर अपनी वापसी के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं। उनकी वापसी व्यवस्था का एक विफल पहलू है, व्यवस्था को इन दुर्घटनाओं की भरपाई करने के साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे हादसे दोहराए न जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देकर सराहनीय कार्य किया है।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

घर में अपने ही जहाँ, हुए कैद भगवान

घर में अपने ही जहाँ,हुए कैद भगवान। निश्चित है होगा वहाँ, परेशान इंसान। मन्दिर के पट बंद हैं, मार्ग सभी वीरान। मुश्किल में है आदमी, कृपा करें भगवान ।। कोरोना ने कर दिया, ऐसा बंटाधार। कठपुतली सा हो गया, सबका ही किरदार ।। **रमेश शर्मा**

सैकड़ों मील पैदल चल कर घर पहुँचने

सैकड़ों मील पैदल चल कर घर पहुँचने की जद्दोजहद कर रहे लोगों को रास्तों से उठा कर उनके घर पहुँचाने की जवाबदेही अख़िर किसकी है। बदनसीब तुम हो या वो ये तो वक्त ही बताएगा। बस इतना ही कहते हैं कि अब लौट कर मत जाना।

राकेश मिश्रा

खास पाती

सोच-समझ कर चल पड़ें,मधुशाला

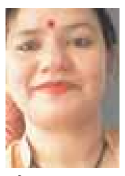

सोच-समझ कर चल पड़ें,मधुशाला जब पाँव। मिटने को आतुर समझ, सिर से घर की छाँव।। मन को करती है भ्रमित,तन को दुख-आगार। क्षय करती है बुद्धि का,किंचित करो विचार।। सुरा सोम से भिन्न है, समझ न एक समान। असुर भाव जब हो प्रबल,करें सुरा का पान।। सतसंगत कर लो सभी,सत्य करो स्वीकार। सृष्टि सुरभि- संयुक्त है, सदा सोम आधार।। पान करो सब प्रात ही, प्राणवायु साभार। नित नूतन देती मही, अति अनुपम उपहार।। नशा करो तो प्रेम का, मदिरा जाओ भूल। अन्तर्मन को साफ कर, मद पर डालो धूल।। दुख भी जीवन के सभी ,बन जायेंगे फूल। मदिरा से मन को हटा,द्विविधा में मत झूल।। **शुभा शुक्ला मिश्रा 'अधर'**

जिज्ञासा का मृत होना, मायूसी का

जिज्ञासा का मृत होना, मायूसी का जीवित होना है इच्छा-शक्ति का क्षीण होना, पतन का संकेत है प्रेम में छलावे का होना, बेगानेपन का तेज़ी से पनपना है और- कविताओं का मौन होना, अनुभूतियों का आत्म-मन्थन होना है। **अनुभूति गुप्ता**

आज मिला मुझे प्राण प्रिये रक्तिम

आज मिला मुझे प्राण प्रिये रक्तिम आभा मुख पर कुंतल घनेरे स्वर्ण समान जीवन का देता संदेश आकुलता को मिला निर्वाण प्रिये आज मिला मुझे प्राण प्रिये भर कर आज पीयूष कलश उर मे स्नेह अभिसार लिए निकल पड़ी उस पथ पर राही मिला प्रीति का प्रमाण प्रिये आज मिला मुझे प्राण प्रिये आबद्ध पुनीत नेह बंधन मे पग पग बढती रहूं अविराम स्निग्ध दृग कोमल हृदय पुलकित पुलकित उच्छ्वास प्रिये आज मिला मुझे प्राण प्रिये। **नम्रता सरन सोना**

वक़्त के साथ बदल जाते हैं भाव

वक़्त के साथ बदल जाते हैं भाव और अहसास मगर ये जरूरी तो नही जो हम समझे वो सही हो कई बार होता है यू भी हमारी कल्पनाएं ही ढक देती हैं वास्तविकता को और हम झूठ को मानने लगते हैं सच निकालने लगते है खुद ही किसी की बातों के मायने और गुनाहगार बना खड़ा कर देते है उसे कठघरे में जानते हो माँ ने बताया था जब हमारा बोलना हो जाये गैरजरूरी न दिखे मोल कही गयी बातों का जब निकलने लगे एक बात के कई अर्थ तब जरूरी हो जाता है ...मौन। **प्रिया वच्छानी**

एक दूजे पर किचड उझालो, संस्कारों

एक दूजे पर किचड उझालो, संस्कारों को कुचल डालो!
इसका दाम अच्छा मिलेगा, बेकार ईमान को बेच डालो!
हमेशा सत्य पर लगेगे प्रश्न झूठ के संग रिश्ता बना लो!
इंसानियत को मारों गोली, आदमियत की अर्थी निकालो!
पता है ना बहुत स्वादिष्ट है, नोच-नोच के देश को खालो
!! **राज चुन्नी शर्मा**

एक वायरस ने साबित कर दिया

एक वायरस ने साबित कर दिया है कि ये देश कितना खोखला है। मजदूरों की स्थिति बयान कर रही है कि दो महीने भी लॉकडाउन की मार झेल नहीं पाये हम। एक तरफ तो हम विकसित होने का दावा करते हैं और दूसरी ओर हमारी जड़ें इतनी खोखली हैं कि एक झटके में कोई भी आपदा हमें उखाड़ फेंक सकती है। जब हमारे देश की नींव ही कमजोर हो तो हम सशक्त कैसे हो सकते हैं। **प्रियंका प्रियदर्शनी**

QUIZ TIME

Ramaquiz

1) 'पागल पंथी सत्याग्रह' कहाँ हुआ था?
(क) बिहार (ख) महाराष्ट्र
(ग) बंगाल (घ) गुजरात

2) 'पुणे सार्वजनिक सभा' की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? (जमशेदपुर / पुणे)

3) भूतल के नीचे का जलस्तर .... कहलाता है।

4) 'बृहत् संहिता' पुस्तक किसके द्वारा लिखी गयी?

5) हाथीगुम्भा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था?

उत्तरमाला-(1) बंगाल (2) पुणे (3) वाटर टेबल (4) वराहमिहिर (5) खारवेल

आज का इतिहास

नयी दिल्ली । भारतीय एवं विश्व इतिहास में 18 मई की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं :- 1703 - डच और अंग्रेज सैनिकों ने जर्मनी के कोलोन शहर पर कब्जा किया। 1756 - ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 1769 - ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। 1794 - ट्रेकोइंग की लड़ाई : फ्रांसीसी सैनिकों ने ब्रिटेन की सेना को हराया। 1804 - नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। 1860 - अब्राहम लिंकन को रिपब्लिकन पार्टी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना गया। 1912 - पहली भारतीय फीचर लेंथ फिल्?म श्री पुंडालिक रिलीज हुई। 1933 - पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा का जन्म।

सड़क की तपिश और पांव के छालों पर चरण पादुका का मरहम

बातों...बातों में...

सुकांत राजपूत

कोविड पॉलिटिक्स...

कोरोना से जंग की बात करने वाले खद्दरधारी अब जीभ लमाए कोविड पॉलिटिक्स में उतर गए हैं। देश क्या और राज्य क्या, कोविड के खिलाफ किसने कितने तीर मारे यह बताने की बजाए एक-दूसरे की कमियां गिनाते नजर आ रहे हैं। नेशनल न्यूज चेनल के डिबेट बॉक्स से लेकर खबरों के पन्नों में बयानवीरों की सबसे बड़ी चिंता है कोविड फंड में कितना आया। राज्य पीएम केयर फंड और वर्ल्ड बैंक से मिली राशि के लिए लालायित हैं तो वहीं केंद्र रेल, विमान से लेकर परिवहन सुविधा तक का पैसा वसूलकर फंड की बजाए टेस्ट किट का लॉलीपॉप थमा रही है।

हालात पर सियासत...

गरीब और मजदूरों के नाम पर सियासत चमकाने का क्रम पूरे

सालभर तक चलेगा। लॉकडाउन, फंसे मजदूरों का मुद्दा और आर्थिक लॉकडाउन के लिए पैसों की दरकार पर ही अब सालभर की सियासत चलानी होगी। इसका नजारा अभी से दिखाई देने लगा है। सत्तापक्ष या फिर विपक्ष की भूमिका में दिख रहे राजनेताओं को मीलों भूखे-प्यासे नंगे पैर अपने घर पहुंचने की कोशिश में गरीब के पैरों के छालों पर बात करने की बजाए अब केंद्र-राज्य के बीच सिर्फ फंड की बात चल रही है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वॉर्ड बनाने से लेकर भोजन के नाम पर केंद्र के बफर स्टॉक से मुफ्त अनाज या फिर कोरोना से जंग के लिए फंड की मांग ही सियासत का नया अंदाज है।

अपनों से यात्रा भत्ता...

वैश्विक महामारी के वक्त भी केंद्र की मोदी सरकार का ऐसा चेहरा सामने आया है जो कई सवाल खड़े करता है। बरबस ही वर्ष 1990 का वक्त याद आता है, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उस वक्त कुवैत में ईराक ने हमला कर कब्जा किया था। उस वक्त हजारों भारतीय वहां फंसे हुए थे। दिलेर राजा मांडा ने फौरे से पेश्तर आदेश किया और चंद दिनों में ही लगातार 500 उड़ानें कुवैत से भारत के बीच संचालित करवा अपने भारतीयों को सुरक्षित देश ले आए थे। मजे की बात यह कि भारत से कुवैत के बीच लाने-ले जाने का यह सिलसिला बिलकुल मुफ्त हुआ। किसी भी देशवासी से एक रुपया भई यात्रा भत्ता नहीं लिया गया था। अब आलम यह है कि अमेरिका से भारतीयों को लाने का किराया प्रति व्यक्ति 1 लाख और ब्रिटेन से यह राशि 50 हजार रुपए वसूली जा रही है। विदेश तो छोड़िए बल्कि भारत के एक से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने-लेजाने का भी पूरा शुल्क राज्यों पर थोपा गया है। कौन है वह जो अपनों की हिफाजत के लिए कीमत वसूल रहा है?

कैश-क्रॉप्स का बफर स्टाक

दूसरी पाली में हमें तो यही बताया, सुनाया और पढ़ाया जा रहा है कि हम शेर हैं, पैसा, खाना देश में पर्याप्त है। कुछ हद तक यह सच भी है कि देश में अनाज का बफर स्टॉक है। इतना कि 84 दिनों तक पूरा देश बैठकर खा सकता है। कैश भी खजाने में इतना है और वर्ल्ड बैंक से इतना मिला है कि हर की जेब भारी हो सकती है। कहने का मतलब यह कि नुक्सान से उबर सकता है। यूएई और अमेरिका से भी टेस्ट किट, वेंटिलेटर बल्क में मिला है। इसमें तुर्रा यह कि हर राज्य के मुख्यमंत्रियों और देश के प्रधानमंत्री फंड में देश के लक्ष्मीपुत्रों से लेकर नौनिहालों तक ने अपना गुल्लक फोड़कर न्यौछावर कर दिया है। इतना होने के बाद भी कौन है वह कृपण जो गरीबों को छाले फूटते तक और भूख से पेट मरोड़ते तक मजबूर कर रहा है?

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरने वाले अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार की सहूलियत एवं सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अपने गांव घर पहुंचने के लिए सीमावर्ती राज्यों से हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाले प्रवासी श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के निशुल्क चाय,नाश्ता, भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही उन्हें राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने की है।

प्रवासी श्रमिकों की सहूलियत एवं सुविधा का ध्यान रखने की इस मुहिम में जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग भी बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहें है। राज्य सरकार के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों एवं समाजसेवियों की संवेदनशीलता की एक बानगी रायपुर के टाटीबंध चौक पर देखने को मिली। प्रवासी श्रमिक परिवारों ने तपती सड़क पर चलने से पांवों में पड़े छाले पर चरण पादुका पहनाकर मरहम लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताया।

यहां यह गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के तीसरे चरण से बेबस अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक हजारों-हजार किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। इन श्रमिकों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरने वाले प्रवासी श्रमिक हमारे मेहमान है। उन्होंने अन्य प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहूलियत एवं सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासी श्रमिकों

मुख्यमंत्री की अपील पर प्रवासी श्रमिकों की सेवा में जुटे जनप्रतिनिधि और समाजसेवी

नंगे पांव छोटा बच्चा चल रहा था पैदल, नजर पड़ते ही विधायक ने पहना दी चप्पल

लॉकडाउन के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। सुबह के पश्चात दोपहर तक तेज गर्मी का अहसास हो रहा है। इस बीच अपने घर को लौट रहे अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों को टेऊन नही चलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों के साथ उनके अपने छोटे बच्चे भी है, जो आवागमन को लेकर परेशानी झेल रहे है। ऐसा ही एक मजदूर परिवार रिंग रोड पर अपने घर को जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई वाहन इंतजार करता दिखा। इस प्रवासी मजदूर के साथ चार-पांच साल का छोटा बच्चा भी था, जिसके पैरों पर चप्पल नही थी, वह अपने माता-पिता के साथ नंगे पांव ही सड़क पर खड़ा था, तभी आवश्यक व्यवस्था और सेवा कार्य के लिए निकले रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय की नजर उस मासूम बच्चे पर पड़ी। विधायक से रहा नही गया उन्होंने तत्काल उस बच्चे के उम्र के हिसाब से चप्पल का इंतजाम किया और उसके पैरों पर पहना दी। विधायक के इस पहल से गर्मी की मार सह रहा मासूम को तत्काल ही राहत मिली, वह बहुत खुश हो गया। मासूम बच्चे के माता-पिता ने भी विधायक श्री उपाध्याय की इस नेक पहल को सराहा और धन्यवाद दिया। उन्होंने टाटीबंध चैक में कई प्रवासी श्रमिकों को चरण पादुकाएं वितरित की और उन्हें मिल रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी।

छग के धनवार, ककना, चेकपोस्ट में पहुंचते ही श्रमिकों को मिली चरण पादुकाएं

कोरोना संकट के कारण प्रवासी मजदूर अपने राज्यों को वापस लगातार लौटना जारी है। मजदूरों को लम्बी दूरी की यात्राओं के दौरान कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रवासी मजदूरों के हितों के ध्यान में रखते हुए सीमाओं के चेक पोस्ट सहित आवागमन के लिए चिन्हित रास्तों में श्रमिकों की सहायता के लिए उचित प्रबंध किये गये हैं। बलरामपुर-रामानुजगंज की सीमा झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश से लगती है, श्रमिक बड़ी संख्या में इन रास्तों से होकर गुजर रहें हैं। जिला प्रशासन द्वारा शुरू से ही श्रमिकों की हर संभव सहायता की जा रही है तथा उन्हें भोजन, पानी, चरण पादुका का वितरण एवं स्वास्थ्य संबंधी निःशुल्क व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

अन्य राज्यों के श्रमिकों की सहूलियत और सहायता में जुटी सरकार

रायपुर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में जब अपनों ने मुंह फेर लिया। मालिकों और ठेकेदारों ने पल्ला झाड़ लिया। ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों की कम्पनियों, फेक्टरियों, मिलों, कल कारखानों, ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं के निर्माण में दिन रात पसीना बहाने वालों श्रमिक बेबस होकर रोते बिलखते अपने-अपने गांवों का सफर तय करने पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े। हजार-हजार ढेड-ढेड हजार किलोमीटर की दूरी को श्रमिकों ने पांव-पांव नापने लगे। देश का शायद ही ऐसा कोई कोना बचा हो जहां के हाईवे और सड़कों पर श्रमिकों का रेला न दिखाई देता हो। बेबस मजदूर अपनी छोटी-मोटी गृहस्थी की गठरी सर पर उठाए, नन्हे-मुन्हे, छोटे बच्चों को कांधे पर लादे अपनी बेबसी की दास्तां खुद बयां कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के सीमाओं पर पहुंचने वाले सभी श्रमिकों के चाय, नाश्ते, भोजन की सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं परिवहन निःशुल्क व्यवस्था ने श्रमिकों के दुख दर्द पर काफी हद तक मरहम लगाने का काम किया है। इस बेबसी के आलम में श्रमिकों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशीलता के सभी कायल है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को, चाहें वो किसी भी राज्य के हो, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मान कर शासन-प्रशासन के लोग उनके सेवा-सत्कार में शिद्दत से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री की अपील पर श्रमिकों की सहायता में राज्य के स्वयं-सेवी, समाज सेवी संस्थाओं, उद्योग और व्यापारिक संगठनों के लोग भी बराबर की साझेदारी निभा रहे हैं। बेबस प्रवासी श्रमिकों को सहूलियत और सहायता पहुंचाने के छत्तीसगढ़ सरकार को इंतजाम को देखकर बरबस इकबाल की यह नज्म याद आती है- हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्द मंदों और जईफों से मोहब्बत करना।

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी बार्डर इलाके के चेकपोस्ट पर देश के अन्य राज्यों से कष्ट दायक सफर तय कर पहुंचने वाले श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने न सिर्फ भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था की है, बल्कि निःशुल्क बस की व्यवस्था कर श्रमिकों को राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने प्रबंध किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का बाघनदी बार्डर जो राजनांदगांव और महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के विभिन्न जिलों से यहां पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को सकुशल उनके राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए 100 बसों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन ने सुनिश्चित की है। बाघनदी बार्डर पर पहुंचने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिक झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल के है, जो छत्तीसगढ़ होते हुए अपने गृह राज्य जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की मदद में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रख रही है। तपती दोपहर और दहकती सड़क पर नंगे पांव चल कर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों का स्वागत सत्कार उन्हें चाय, नाश्ता देकर और चरण पादुका पहनाकर किया जा रहा है। कमोवेश यहीं व्यवस्था राज्य के सभी चेकपोस्टों पर शासन-प्रशासन ने सुनिश्चित की है। राज्य के रेंगाखार, चिल्फी, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, अंबिकापुर, रामानुजगंज आदि बोर्डर पर पहुंचने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को उनके गृह जिला तथा अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को भी राज्य की सीमा तक सकुशल पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था शासन-प्रशासन ने की है।

राजधानी रायपुर में स्थित टाटीबंध का

अपने और बेगाने का फर्क नहीं, सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभाने में जुटे लोग

सैकड़ों किलोमीटर दूर से भूखे-प्यासे पहुंचे प्रवासी श्रमिकों को मिला छत्तीसगढ़ सरकार का सहारा

भोजन-पानी, राशन सामग्री पाकर तृप्त हुए श्रमिक

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। सैकड़ों किलोमीटर दूर से भूखे-प्यासे जैसे-तैसे अपने घर जाने की आस में निकले श्रमिकों को छत्तीसगढ़ पहुंचकर ऐसा लगा मानों मंजिल ही मिल गई। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले श्रमिक यहां की व्यवस्था से काफी खुश है। ऑखों में आसू और ह्दय में पीड़ा लिए दो-दो, तीन-तीन दिनों से भूखे-प्सासे चलते हुए श्रमिक जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तब इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार और स्वयं सेवी संस्थाओं से हर प्रकार का सहयोग मिला। इन श्रमिकों ने अपनी सारी पीड़ा बिसार दी और इस मानवीय पहल को सराहते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताया।

रायपुर शहर के टाटीबंध चौक पर पहुंचे कई श्रमिकों ने बताया कि घर पहुंचने की आस में श्रमिक चिलचिलाती धूप हो या गरजते-चमकते बादल सैकड़ों किलोमीटर दूर देश के विभिन्न राज्यो से भूखे-प्यासे, चलते, दौड़ते, थकते किसी तरह अपनों के साथ, अपनों के पास पहुंचने सैकड़ों मजदूर अपने छोटे-छोटे बच्चों को कधों अथवा कमर में ढोते आखों में आसू, और दिल में पत्थर लेकर निकल पड़ें थे। उन्हें छत्तीसगढ़ पहुंचकर बहुत राहत महसूस हुई।

प्रवासी श्रमिक श्री मुन्ना सिवारे और साथियों ने बताया कि वे दो-तीन दिनों से भूखे-प्यासे जैसे-तैसे अहमदनगर से अपने घर झारखंड जाने के लिए निकले है। उन्होंने बताया कि वे मिठाई की दुकान में जलेबी बनाने का काम करते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से वहां फंस गए थे। जेब में कुछ पैसे थे, तब तक कुछ खा-पीकर चलते रहे, लेकिन पैसे खत्म हो जाने पर हमारी परेशानी बढ़ गई। किसी तरह हम रायपुर शहर के टाटीबंध पहुंचे। यहां पहुंचते ही ऐसे लगा मानों सब कुछ मिल गया। यहां प्रशासन और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा हम सबको खाने के लिए भोजन, केला, बिस्किट पानी, छाछ, पूरी-सब्जी मिली और जाने के लिए बस की व्यवस्था कराई गई।

गृह राज्य जाने बसों की हुई व्यवस्था, श्रमिकों ने माना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार

साइकिल से सफर हो गया था मुश्किल, अब बस से पहुंच जाएंगे मंजिल

पुणे से ओडिशा लौटते मजदूरों को छत्तीसगढ़ आते ही मिली बस

ओडिशा के कंधमाल जिला के रहने वाले हेमंत, कपूना बेहरा और जसवंत बगोरती के पास जब अपने गांव में कुछ काम नही था तब इन तीनों ने शहर जाकर कुछ नया काम करने और कुछ रूपये जोड़ने की ठानी। हेमंत को अपनी बहन की शादी के लिए भी कुछ रकम जुटानी थी। इसलिए लगभग चार महीना पहले महाराष्ट्र के पुणे में जाकर बोरिंग करने का काम एक ठेकेदार से जुड़कर शुरू किया। अभी दो माह ही हुए थे, उनका बुना हुआ सपना पूरा हो पाता इससे पहले ही देश में अचानक से लॉकडाउन हो गया। कुछ दिन में लॉक डाउन खुल जायेगा और काम फिर से शुरू हो जाएगा,कुछ इन्हीं उम्मीदों के साथ इन तीनों दोस्तों ने एक कमरे में बिना किसी काम के दो माह तक अपना दिन गुजारा। इस बीच जो कमाये थे वह बची खुची रकम भी खर्च हो रही थी। हाथ में बहुत कम पैसे बचे थे, लॉकडाउन कब खुलेगा, यह भी कुछ अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था, आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और अन्य सैकड़ों मजदूरों की तरह ये तीनों साथी पुणे से नया-पुराना साइकिल खरीदकर ओडिशा के लिए निकल पड़े।

सफलता का श्रेय परिवार को देती है आयुषी

मुंबई, । अपनी मेहनत और लगन से हॉलीवुड में सशक्त पहचान बनाने वाली आयुषी छाबड़ा अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार वालों को देती है। ग़ाज़ियाबाद जैसे छोटे शहर की रहने वाली आयुषी ने जनवरी 2020 में अमेरिकन टेलिविज़न स्टार ट्रेक : पिकार्ड में पेल नाम की शानदार भूमिका के साथ अपने अभिनय करियर का आग़ाज़ किया।

इस सफलता के अलावे आयुषी अपनी पहली भारतीय फ़िल्म '919' में एक दमदार किरदार में दिखेगी। अमेरिकन लेखक- निर्माता सेंडि साय की इस तेलुगु फ़िल्म का टाइटल '919' है और इस साल के अंत में अमेरिका और भारत में रिलीज़ होगी। मॉडल से अभिनेत्री बनी भारतीय मूल की साउथ अफ्रीकन अभिनेत्री आयुषी ने अपनी प्रतिभा के बल पर जुनून और कठिन मेहनत से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत रही है। आयुषी छाबड़ा अपनी सफलता का पूरा श्रेय भारत में हुए अपने परवरिश और अपने पूरे परिवार को देती हैं। आयुषी अपने संयुक्त परिवार को याद करते हुए कहा , मैं जहाँ भी जाऊँ अपने परिवार के तमाम सदस्यों को खूब मिस करती हूँ।

अपने पसंदीदा यादों में से एक है, पूरा परिवार रविवार को एक साथ होते हैं और मज़ेदार क़िस्से कहानियों का दौर चलता है। आयुषी ने कहा, मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने दिल में भारत को ले कर घुमती हूं, और भले ही मैं अभी जिस जगह पर भी रहूँ ,एक दिन के लिए भी भारत में अपने प्रियजनों या उस शहर को नहीं भूल पाती हूँ, जिसने मुझे इतना प्यार और सबसे खूबसूरत यादें दी।

फीस में कटौती के लिये तैयार हैं तापसी पन्नू

मुंबई, । बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू लॉकडाउन के बाद अपनी फीस में कटौती के लिये तैयार है। कोरोना वायरस के चलते बॉलीवुड इंडस्ट्री का पूरा काम बंद पड़ा है। कई फिल्मों की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। शूटिंग बजट प्रभावित हो रही है और ऐक्टर्स फीस में कटौती कर रहे हैं। तापसी पन्नू ने कहा, अभी तो क्योंकि कोई शूटिंग नहीं हो रही तो कोई सैलरी नहीं मिल रही। और तैयार हूँ आगे हमारी सैलरी में भी कटौती होगी। फिल्म प्रोड्यूसर्स को अपनी फिल्मों को सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने पर थिएटर चेन ने असंतोष व्यक्त किया है। इस पर तापसी ने कहा है, मैं हैरान नहीं हूं कि वे नाराज है। गुस्सा जायज है लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि समय का पहिया किस तरह मुड़ता है।

शाहरूख ने लॉकडाउन से सीखा कुछ ख़ास

मुंबई, । बॉलीवुड के किंग खान शाहरूख खान ने लॉकडाउन के दौरान पांच जरूरी बातें सीखी है। शाहरुख भी लॉकडाउन में अन्य सेलेब्स की तरह अपने घर पर हैं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फैंस से लगातार रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने ने इंस्टाग्राम हैंडल पर लॉकडाउन से सीखी पांच जरूरी बातों को लेकर लिखा। शाहरुख ने अपनी सेल्फी के साथ कुछ पॉजिटिव बातें इंस्टाग्राम पर लिखी हैं। शाहरुख खान ने कहा कि इस लॉकडाउन ने काफी सिखाया है। उन्होंने लिखा, हम लंबे समय से अपनी कितनी इच्छाओं को बिना पूरा करे रह रहे हैं, लेकिन अब अहसास हुआ कि वो कभी इतनी जरूरी थी ही नहीं। अब समझ आ गया है कि हमें अपने करीब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी जरूरत है जिन से आप इस लॉकडाउन में बात कर सकें। अब एक बार अगर समय रुक जाए तो अपनी सभी उन झूठी असुरक्षाओं को भुला फिर जिंदगी को जीना है। जिन से कभी लड़े थे, उनके साथ हंसना है। इन सब के ऊपर प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, उसकी कीमत कभी कम नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए।

प्रवासी मजदूरों की मदद करना हमारा कर्तव्य : सोनू सूद

मुंबई, । बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूर को देश के दिल की धड़कन बताते हुए कहा कि उनकी मदद करना सभी का कर्तव्य है। सोनू ने कहा ,मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रवासी मजदूरों के लिए मदद करूं, जोकि हमारे देश के दिल की धड़कन हैं। हमने प्रवासियों को अपने परिवारों और बच्चों के साथ रोड पर चलते देखा है। हम सिर्फ एयर कंडिशनर में बैठकर ट्वीट नहीं कर सकते या अपनी चिंता नहीं दिखा सकते हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी, अन्यथा उन्हें यह भरोसा नहीं होगा कि कोई उनके लिए खड़ा है। इसलिए मैं उनकी यात्रा के लिए विभिन्न राज्यों से अनुमति लेकर चीजें उपलब्ध करवाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अभिनेता ने कहा, अब मुझे बहुत सारे मैसेज और सैकड़ों ई-मेल रोज़ मिलते हैं जो कहते हैं कि वे घर जाना चाहते हैं और मैं सुबह से शाम तक नॉन-स्टॉप काम कर रहा हूं।

इस लॉकडाउन के दौरान मेरा यहीं काम बन

लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहने के लिए 23 घंटे रखा उपवास

मुंबई, । बॉलीवुड के माचो मैन ऋतिक रोशन ने लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहने के लिए 23 घंटे का उपवास रखा हैं। ऋतिक रोशन लॉकडाउन के दौरान भी अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए हुए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की कि कैसे उन्होंने 23 घंटे का उपवास किया। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, '23 घंटे का उपवास। इसमें एक नई सेल्फी और एक ऐप का स्क्रीनशॉट है जो उनकी फिटनेस पर नज़र रखता है। सेल्फी में ऋतिक कैमरे के लिए पलक झपकाते दिखाई दे रहे हैं। ऋतिक के प्रशंसक उनके शानदार लुक से एक बार फिर प्रभावित हुए। एक फैन ने लिखा, 'खूबसूरत फोटो सर', वहीं एक अन्य ने लिखा, 'सुंदर लग रहे हों।ऋतिक इन दिनों अपने दो बेटों हरेन, हृदान और अपनी पूर्व पत्नी सुजैन खान के साथ लॉकडाउन में सेल्फ-आइसोलेशन में है।

पेरु के फुटबॉल खिलाड़ी जैफैरसन फरफान कोरोना से संक्रमित

लीमा। पेरु और लोकोमोटिव मॉस्को फुटबॉल क्लब के फॉरवर्ड खिलाड़ी जैफैरसन फरफान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 35 वर्षीय खिलाड़ी के स्वास्थ्य के बारे में हालांकि ज्यादा जानकारी नहीं दी गयी लेकिन पेरु मीडिया के अनुसार उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। लोकोमोटिव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फरफान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और हम उनके जल्द स्वस्थ्य होने की कामना करते हैं। फरफान ने पेरु के लिए 95 मैच खेले हैं और वह पिछले साल ब्राजील में कोपा अमेरिका में खेलते समय चोटिल हो गए थे जिसके बाद क्लब के लिए इस सत्र में अब तक नहीं खेल पाए थे। रुस प्रीमियर लीग को 21 जून से दोबारा शुरु होना है। इसे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मार्च में स्थगित कर दिया गया था। लोकोमोटिव 16 टीमों में अभी दूसरे स्थान पर है और अभी आठ मैच बाकी हैं।

दर्शकों के बिना शुरु होगी ईरान फुटबॉल लीग : रुहानी

तेहरान । ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने कहा है कि रमजान के बाद दर्शकों के बिना ईरान फुटबॉल लीग शुरु की जाएगी। कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में खेल गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं और इसका असर ईरान में भी बखूबी पड़ा है। रुहानी ने कहा कि फुटबॉल लीग रमजान के महीने के बाद शुरु की जाएगी लेकिन इसे दर्शकों के बिना खेला जाएगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का आयोजन सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करके किया जाएगा। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ईराज हरिरची ने भी कहा था कि हम इस सत्र को छह सप्ताह में खत्म कर सकते हैं और टीम को टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए तीन सप्ताह का समय लगेगा।

धोनी-सचिन ने करियर के दौरान मेरा मनोबल बढ़ाया : अश्विन

नई दिल्ली, । भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि उनके करियर में उतार-चढ़ाव के दौरान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनका मनोबल बढ़ाया था। अश्विन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से एक हैं। वह अपनी मानसिक और रणनीतिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कई बार करियर में उन्हें उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा और उस वक्त धोनी तथा सचिन जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने उनकी

काफी मदद की और उन्हें प्रेरित किया।

विश्वकप में सचिन ने बढ़ाया मनोबल

ऑफ स्पिनर ने बताया कि 2011 विश्वकप के दौरान सचिन ने उनका मनोबल बढ़ाया था क्योंकि पहली पसंद ऑफ स्पिनर होने के कारण हरभजन सिंह को ज्यादा मौके मिलते थे। उस वक्त किस तरह सचिन ने उन्हें प्रेरित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। अश्विन ने स्टार स्पोटर्स की नयी सीरीज माइंड मास्टर्स एमफोर में डब्ल्यूवी रमन से कहा, सचिन उस दौरान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम नेट्स पर अच्छी गेंदबाजी करते हो, ऐसी ही गेंदबाजी मैच के दौरान भी करना। उन्होंने बताया कि 2013 चैंपियंस ट्राफी के दौरान जब वह अपने अभियान की शुरुआत उम्मीद के अनुरुप नहीं कर पाए थे तो उस वक्त धोनी ने उनका मनोबल बढ़ाया था और इसके बाद उन्होंने टीम की जीत में अहम योगदान दिया था। अश्विन ने कहा, धोनी चैंपियंस ट्राफी के पहले मैच में मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुम बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। उस वक्त मैंने विकेट भी नहीं लिए थे। कार्यक्रम में वेस्टइंडीज के लीजेंड क्रिकेटर ब्रायन लारा ने मानसिक कौशल ट्रेनिंग पर कहा, ÷प्रतिभा एक चीज है लेकिन इसके लिए मानसिक तौर पर मजबूत होना जरुरी है जो खेल का एक हिस्सा है। मैंने इस बात पर काफी ध्यान केंद्रित किया है। मेरे अनुसार एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए आपको अपने मानसिक मजबूती पर ध्यान देने की जरुरत है।

देश के लिए बंदूक भी उठा सकता हूं : हरभजन

नई दिल्ली । पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद आफरीदी की संस्था की मदद करने के बाद लोगों के निशाने पर आए भारत के अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह का कहना है कि जरुरत पड़ने पर वह देश के लिए बंदूक भी उठा सकते हैं। हरभजन और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आफरीदी की संस्था के लिए मदद की अपील की थी जिसके बाद देशभर में इन दोनों खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना हुई थी।

आफरीदी शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर गए और वहां उन्होंने भारत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे। उनके इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एक बार फिर हरभजन और युवराज को निशाने पर लिया।

हरभजन ने इंडिया टूडे से कहा, ÷मैं इस देश में जन्मा हूं और यहीं मरूंगा। मैं अपने देश के लिए 20 वर्षों से अधिक समय से खेल रहा हूं और भारत के लिए कई बार मुकाबले जीते हैं। कोई यह नहीं कह

सकता कि मैंने कभी देश के खिलाफ कुछ गलत किया है। आज या कल कभी भी देश को मेरी जरुरत होगी, चाहे सीमा पर ही क्यों ना हो मैं वो पहला व्यक्ति हूं जो अपने देश के लिए बंदूक भी उठा लूंगा। उन्होंने कहा, आफरीदी ने हमारे देश और प्रधानमंत्री के लिए जो कहा वो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ईमानदारी से कहूं तो आफरीदी ने हमसे उनकी चैरिटी की मदद करने की अपील की थी और अच्छे भाव से इंसानियत के नाते हमने उनकी मदद की।

खिलाड़ियों को दर्शकों के बिना खेलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए : नीशम

वेलिंगटन, । न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी नीशम का मानना है कि खिलाड़ियों को दर्शकों के बिना खेलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के खतरे के कारण दुनियाभर में खेल गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई है और इसे दर्शकों के बिना शुरु करने पर बहस जारी है। इस बीच नीशम का मानना है कि क्रिकेट नहीं होने से विभिन्न क्रिकेट बोर्ड को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अगर दर्शकों के बिना मैच कराए जा सकते हैं तो इससे खिलाड़ियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोरोना के कारण क्रिकेट

गतिविधियां ठप्प होने से पहले न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच दर्शकों के बिना वनडे मुकाबला खेला गया था और नीशम भी उस मैच का हिस्सा थे। नीशम ने क्रिकइंफो के वीडियोकास्ट में कहा, सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि दर्शकों के बिना मैच कराए जा सकते हैं तो खिलाड़ी होने के नाते हमें इसे स्वीकार करना होगा। उन्होने कहा, मेरे ख्याल से मैच नहीं होने कारण विभिन्न क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हो रहा है और उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम दर्शकों के बिना मैच खेल सकते हैं तो मेरे ख्याल से खिलाड़ियों को इससे परेशानी नहीं हो चाहिए। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने टी-20 विश्वकप की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि टीम ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े टूर्नामेंटों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

मुंबई इंडियंस मेरे करियर की सबसे पेशेवर टीमः रोहित

मुंबई, । भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि उनके करियर में मुंबई सबसे पेशेवर टीम है। कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में क्रिकेट गतिविधियां ठप्प पड़ी हुई हैं। ऐसे में रोहित ने बंगलादेश के कप्तान तमीम इकबाल के साथ बातचीत की जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ अपने अनुभव को साझा किया। रोहित के नेतृत्व में मुंबई ने चार बार आईपीएल का खिताब जीता

है। रोहित ने कहा, मुंबई इंडियंस अपने खिलाड़ियों की बेहतर तरीके से देखभाल करता है। यह मेरे करियर की सबसे पेशेवर टीम में से एक है जिसमें मैं शामिल रहा हूं। जब मेरा इस फ्रेंचाइजी के साथ तीसरा वर्ष था तभी मैं इस टीम की कप्तानी करना चाहता था। मुझे 2013 में आईपीएल के बीच में कप्तानी सौंपी गयी। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा के ब्रांड एम्बेसेडर रोहित ने चर्चा के दौरान पुर्तगाल के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तारीफ की। उन्होंने कहा, ÷रोनाल्डो को कौन प्यार नहीं करता। वह किंग हैं। उन्होंने अपने करियर में जो उपलब्धि हासिल की है वो वाकई शानदार है। वह जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहां से आकर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं है।

राज्यों की उधार लेने की सीमा 3 फीसदी से 5% तक बढ़ाई

नई दिल्ली (ए.)। कोरोना लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की बारीकियों को बताने के दौरान आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सरकारों के लिए बड़ा ऐलान किया। कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों की उधार लेने की सीमा बढ़ा दी है। केंद्र ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी कर दिया है।

यह केवल 2020-21 के लिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य 2020-21 में 6.41 लाख करोड़ रुपये 3 फीसदी राज्य के जीडीपी के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे। अभी तक राज्यों ने केवल 14 फीसदी ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86 फीसदी नहीं उठाया है। लेकिन कोरोना के मद्देनजर सरकार ने राज्यों को 2020-21 में राज्यों के जीडीपी का 5 फीसदी कर्ज राज्य ले सकते हैं ये केवल एक साल के लिए है। इससे राज्यों को अतिरिक्त 4.28 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त रकम मौजूद होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दो प्रतिशत की बढ़ोतरी में आधा फीसदी की बढ़ोतरी बिना शर्त की गई है यानी अपने जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत तक राज्य बेरोक-टोक उधारी ले सकेंगे।

अगले एक प्रतिशत में से 0.25 प्रतिशत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के लिए, 0.25 प्रतिशत कारोबार की आसानी के लिए, 0.25 प्रतिशत बिजली वितरण के लिए और 0.25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के लिए लिया जा सकेगा। इन चार में से तीन मानकों का लक्ष्य हासिल होने पर ही राज्य को अंतिम 0.5 प्रतिशत उधारी दी जायेगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के अनुरोध पर रिजर्व बैंक ने राज्यों को दिये जाने वाले ओवरड्राफ्ट के नियमों में बदलाव किया है। अब राज्य लगातार 14 दिन की बजाय 21 दिन तक ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तिमाही में वे कुल 32 दिन की बजाय अब 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट रख सकेंगे। इसके अलावा, निर्मला सीतारमण ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते दिनों कोरोना वायरस को रोकने के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया था। इसमें 4113 करोड़ रुपए राज्यों को दिए गए। 3750 करोड़ रुपए जरूरी वस्तुओं पर खर्च किए गए। टेस्टिंग किट्स और लैब के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए। कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया।

न्यूज गैलरी

पैकेज से मजबूत होगा नागरिक उड्डयन क्षेत्र : पुरी

नई दिल्ली,। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' के चौथे चरण में वायु क्षेत्र, हवाई अड्डों और एमआरओ के लिए की गयी घोषणाओं का स्वागत करते हुये कहा है कि इससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र मजबूत होगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित क्रमिक सुधारों से देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को गति मिलेगी। इन उपायों से हवाई यात्रियों और अन्य सभी हितधारकों को लाभ होगा तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निषिद्ध वायु क्षेत्र में कमी लाने से देश के नागरिक उड्डयन की दक्षता बढ़ेगी। समय तथा विमान ईंधन की खपत घटने से विमान सेवा कंपनियों को सालाना एक हजार करोड़ रुपये की बचत होगी। इससे पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड स्तर पर

मुंबई । देश का विदेशी मुद्रा भंडार 08 मई को समाप्त सप्ताह में 4.23 अरब डॉलर बढ़कर 485.31 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले एक मई को यह समाप्त सप्ताह में 1.62 अरब डॉलर बढ़कर सात सप्ताह के उच्चतम स्तर 481.08 अरब डॉलर पर पहुँच गया। 24 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में यह 11.3 करोड़ डॉलर की गिरावट के साथ 479.46 अरब डॉलर रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी साप्ताहिक आँकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़े घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में आठ मई को समाप्त सप्ताह के दौरान 4.23 अरब डॉलर की वृद्धि हुई और सप्ताहांत पर यह 447.54 अरब डॉलर पर रहा। इस दौरान स्वर्ण भंडार 1.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 32.29 अरब डॉलर हो गया।

खबरी की कोविड-19 हेल्पलाइन को मिला भारी प्रतिसाद

नई दिल्ली । हिंदी डिजिटल ऑडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म खबरी ने कहा है कि दृष्टिबाधितों के लिए शुरू कोविड -19 हेल्पलाइन को बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है और प्रति दिन करीब 2200 सेवा अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इसके लिए शुरू अभियान का एक महीना हो चुका है। यह महामारी के दौरान भारत के दृष्टिबाधित आबादी की जरूरतों को पूरा करने के विशेष कोविड-19 हेल्पलाइन पोर्टल / प्लेटफॉर्म है। कुल प्राप्त सेवा अनुरोधों में से अधिकांश (60 फीसदी) महाराष्ट्र से आए। कुल अनुरोधों में से लगभग 80फीसदी किराने और भोजन के लिए थे, जबकि 19 फीसदी अनुरोध वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए थे।

कोरोना की वजह से भारत में 13.5 करोड़ लोग हो जाएंगे बेरोजगार

12 करोड़ लोग हो जाएंगे गरीब: रिपोर्ट

नई दिल्ली (ए.)। कोरोना वायरस महामारी अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक साबित हुआ है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से भारत में 13.5 करोड़ लोगों का रोजगार छिन सकता है तो 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। उपभोक्ताओं की आमदनी, खर्च और बचत पर इसका बुरा असर होगा।

भारत के कमजोर तबगे पर पड़ेगा

इंटरनेशनल मैनेजमेंट कंस्लटिंग फर्म अर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर भारत के कमजोर तबगे पर पड़ेगा। रोजगार छिनेगा, गरीबी बढ़ेगी और प्रतिव्यक्ति आय कम होगी। इससे जीडीपी में तेज गिरावट आएगी।

जीडीपी ग्रोथ 0.8 पर्सेंट रहेगी

रिपोर्ट में कहा गया है, ''कोविड-19 के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए हमारा अनुमान है कि भारत के मामले में डब्ल्यू शेप रिकवरी होगी। इसकी वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 10.8 पर्सेंट का संकुचन होगा और 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ 0.8 पर्सेंट रहेगी।''

देश में अब तक 2,800 लोगों की मौत

भारत में कोरोना वायरस केसों की संख्या 90 हजार के पार चली गई है और देश में अब तक 2,800 लोगों की मौत हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी दर 7.6 पर्सेंट से बढ़कर 35 पर्सेंट तक जा सकती है। इससे 13.6 करोड़ लोगों का रोजगार छिन जाएगा और देश में कुल 17.4 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। लोगों को गरीबी से निकालने के अभियान को झटका लगेगा और करीब 12 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे, जबकि 4 करोड़ बेहद गरीब हो जाएंगे। अर्थर डी लिटिल के इंडिया और साउथ एशिया मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ बार्निक चितरन मित्रा ने कहा, ''वित्त वर्ष 21 में संभावित 10.8 पर्सेंट संकुचन के साथ भारत डब्ल्यू शेप रिकवरी की ओर बढ़ रहा है।

केन्द्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण

नई दिल्ली (वार्ता)। सरकार ने केन्द्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातर चौथे दिन संवाददाताओं से चर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे बिजली वितरण और आपूर्ति का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवायें मिलेगीं और बिजली वितरण दक्षता में सुधार होगा।

कोरोना के दबाव में शेयर बाजार

मुंबई (वार्ता)। सराकर द्वारा अर्थव्यवस्था में गति लाने के उद्देश्य से 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने की घोषणा के बावजूद बीते सप्ताह भी शेयर बाजार पर कोरोना वायरस का प्रकोप बना रहा है और अगले सप्ताह भी बाजार में तेजी आने की संभावना बहुत कम दिख रही है। समीक्षाधीन अवधि में बीएसई का सेंसेक्स 1.72 प्रतिशत अर्थात 544.97 अंक टूटकर 31097.73 अंक पर टिका। इस दौरान एनएसई का निफ्टी 114.65 अंक अर्थात 1.24 प्रतिशत गिरकर 9136.85 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों में जहां गिरावट देखी गयी वहीं छोटी और मझौली कंपनियों में लिवाली हुयी। बीएसई का मिडकैप 0.67 प्रतिशत बढ़कर 11500.32 अंक पर और स्मॉलकैप 0.47 प्रतिशत बढ़कर 10688.86 अंक पर रहा। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस का प्रभाव का अब भारतीय बाजार पर कम हो रहा है बल्कि घरेलू स्तर पर कोरोना वायरस के मामलों में हो रही बढोतरी से शेयर बाजार पर अधिक दबाव बना है। यहीं कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 20लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के साथ ही कई नियमों को उदार बनाये जाने के बावजूद भी निवेशधारणा को बल नहीं मिल पर रहा है। विश्लेषकों ने कहा कि अगले सप्ताह भी शेयर बाजार पर कोरोना वायरस का असर बना रह सकता है।

क्योंकि अब जहां जहां प्रवासी

कोरोना की वजह से कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया से एक साल तक छूट : वित्त मंत्री

नई दिल्ली (ए.)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्ज की किस्तें चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत एक साल तक कार्रवाई से बचाने की रविवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत एक साल तक कोई नई दिवालिया प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। कोराना से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने और आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के मेगा पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणाओं में आईबीसी संबंधी यह प्राधान भी शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही, कोरोनो वायरस से संबंधित ऋण को डिफॉल्ट की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को लाभ पहुंचाने के लिए दिवाला शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए फंसे कर्ज की न्यूनतम राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा। उन्होंने कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को गैर-आपराधिक बनाए जाने की भी घोषणा की। इसके तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के बारे में जानकारी देने में चूक, निदेशक मंडल की रिपोर्ट की अपर्याप्तता, शेयर बाजारों को सूचना देने में देरी, सालाना आम बैठक में देरी समेत कई प्रक्रियात्मक चूकें तथा मामूली तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं। अर्थ दंड या हर्जाने के साथ समाधान योग्य उल्लंघनों में अधिकांश को आंतरिक न्याय निर्णय प्रक्रिया के तहत रखा जाएगा। इस संबंध में अध्यादेश जारी किया

प्रथम पृष्ठ का शेष

गरीबों, मजदूरों, किसानों के

योजना शहरी के अंतर्गत 8 हजार 241 हितग्राहियों को 82 करोड़ 41 लाख और संबल योजना में 1963 हितग्रहियों को 41 करोड़ 33 लाख ट्रांसफर किये गये। शासन ने सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की महिलाओं को आहार अनुदान योजना अंतर्गत 2 लाख 26 हजार 362 हितग्राहियों को 44 करोड़ 60 लाख और 8.85 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में 177 करोड़ रूपये ट्रांसफर किये। राज्य के बाहर फँसे एक लाख 31 हजार श्रमिकों को 13 करोड़ 10 लाख की राशि ट्रांसफर की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 46 लाख हितग्राहियों को 562 करोड़ की राशि अंतरित की गई। मध्यान्ह भोजन योजना में 87 लाख बच्चों के अभिभावकों के खातों में 117 करोड़, 2 लाख 10 हजार रसोईयों को 42 करोड़ की राशि दी गई। विभिन्न छात्रवृत्तियों के अंतर्गत 52 लाख हितग्राहियों के खातें में 430 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई।

मुख्यमंत्री चौहान द्वारा मृतक

घटना है। मजदूर पति-पत्नी अपने दो मासूम बच्चों के साथ मोटरसाईकिल से घर वापस लौट रहे थे, तभी सेंधवा बार्डर के पास एक ट्रॉले ने उनको टक्कर मार दी जिससे पति-पत्नी की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के एक-एक मजदूर को प्रदेश वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके लिए बड़ी संख्या में ट्रेन एवं बसें चलाई जा रही है तथा उन्हें घर तक पहुंचाया जा रहा है। कोई भी मजदूर जल्दी न करे, पैदल न चले, हम हर मजदूर को शीघ्र ही उसके घर पहुंचायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बाहर के प्रदेशों के भी मजदूर ब?ी संख्या में है। साथ ही मध्यप्रदेश देश का हृदय स्थल होने से विभिन्न प्रांतों के मजदूर अपने राज्य में लौटने के लिए मध्यप्रदेश से होकर गुजरते हैं। ये सब मजदूर हमारे अतिथि हैं। हम इन्हें पैदल नहीं चलने देंगे। साथ ही इन्हें भूखा भी नहीं सोने देंगे। हमने इन मजदूरों को राज्य की सीमा तक पहुंचाने के लिए लगभग एक हजार बसें रोज चलाई हैं, जो इन्हें वहाँ तक छो? रही हैं। इसके साथ ही सबके भोजन, नाश्ते आदि की भी व्यवस्था की गयी है। इस कार्य में प्रशासन के साथ जनता भी पूरा सहयोग कर रही है।

भोपाल में 38 संदिग्ध

लौटे 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। रविवार को 6 मए मामले मिलने का साथ अब थ्री ईएमई सेंटर में संक्रमित मरीजों की संख्या 25 हो गई है। सभी का हमीदिया में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इन संक्रमित लोगों के सैंपल एक बार से लेकर क्रास चैक कराने वाली है। हालांकि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है। रविवार को आई रिपोर्ट में 10 सदस्य 3 अलग-अलग परिवारों के बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ को पहले से ही आइसोलेट किया गया थो कुछ क्वारैंटाइन में थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोपहर में सभी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। इसी के साथ परिवार के अन्य लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित 27 व्यक्ति आज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर रवाना हो गए। ये व्यक्ति यहां चिरायु मेडिकल कालेज अस्पताल से खुश होकर अपने घर रवाना हुए। अस्पताल के कर्मचारियों और चिकित्सकों ने कोरोना पर विजय पाने वाले इन व्यक्तियों को खुशी खुशी रवाना किया।

ये राज्य पहले ही...

मिले सुझावों पर विचार करने के बाद लॉकडाउन-4 के लिए दिशानिर्देशों का खाका तैयार किया गया। ज्यादातर राज्यों ने इस महीने के आखिर तक लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया है।

निजी कंपनियों को...

रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। दोनो मंत्रियों ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार नई लोक उपक्रम नीति लायेगी जिसमें सभी सेक्टरों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोला जायेगा। लोक उपक्रम चुनिंदा रणनीतिक क्षेत्रों में ही कारोबार कर सकेंगे। इन सेक्टरों को नोटिफाई किया जायेगा। इन सेक्टरों में भी कम से कम एक और अधिक से अधिक चार लोक उपक्रमों की ही मौजूदगी होगी। इन क्षेत्रों में भी निजी कंपनियाँ कारोबार कर सेकेंगी। अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोक उपक्रमों का निजीकरण किया जायेगा। यदि किसी रणनीतिक क्षेत्र में चार से अधिक सार्वजनिक कंपनी होगी तो उनका विलय या निजीकरण किया जायेगा।

अब पीएम-ई विद्या...

स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीतारमण ने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं जिनमें डीटीएच चैनलों के अलावा रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया जाएगा।

आज से लॉकडाउन...

सरकार की ओर से आदेश विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। एनडीएमए ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उसका कहना है कि देश में लॉकडाउन के बारे में नेशनल एग्जिक्यूटिव कमेटी (एनईसी) ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 10 (2) के तहत समय-समय पर ऑर्डर और स्पष्टीकरण जारी किए हैं। लॉकडाउन का पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन-2 और 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन-3 था। पहले चरण में केवल जरूरी सामान के लिए छूट थी। लॉकडाउन-2 में हॉटस्पॉट छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन-3 में कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति दी गई थी। इस दौर में देश में जहां-तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें और बसें भी चलाई गईं। इसके अलावा राजधानी के रूट पर 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं।

आज का भविष्यफल

मेष: आज आपका दिन विशेष रूप से लाभदायी है। निवेश, व्यापार, नौकरी, विद्या सभी क्षेत्रों में आज लाभ ही लाभ के संकेत हैं, सभी कार्य फलीभूत होंगे। मगर सेहत का इस वक्त आपको विशेष ध्यान रखना होगा।

वृषभ: आप आज हर काम सरलता से संपन्न कर पाएंगे। नौकरी में आपके उच्च पदाधिकारी खुश रहेंगे। कार्य की व्यस्तता रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर से ऑफिस का काम करते हुए परिवार के साथ भी तालमेल बैठा सकेंगे।

मिथुन: भाग्य के साथ पूर्वनिर्धारित कार्य की तरफ आज आपको प्रयास करना होगा। धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहने की संभावनाएं बन रही हैं।

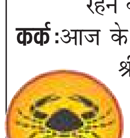

कर्क: आज के दिन किसी भी नए कार्य का श्रीगणेश न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा से परहेज करें, वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। अगर कोई जरूरी कार्य न हो तो घर से बाहर निकलें और जिन लोगों को बाहर का काम है।

सिंह: आज आपका दिन आनंद में बीतेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी और जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रिय व्यक्ति की राय पर विशेष ध्यान दें।

कन्या: सुखशांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अधूरे कार्य संपन्न होंगे। कोई शुभ सूचना मन को प्रसन्न रखेगी। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमों में जीत आपके लिए खुशी का कारण बन सकती है।

तुला: आज साहित्य एवं कला में आपकी रुचि रहेगी। मन में कल्पना की तरंगे उठेंगी। बौद्धिक चर्चाओं में भाग अवश्य लें। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी।

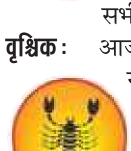

वृश्चिक: आज आपकी मन:स्थिति नकारात्मकता की ओर प्रेरित करेगी। मन को सबल रखें। परिवार में क्लेशमय वातावरण से मन खिन्न हो सकता है।

धनु: मानसिक रूप से आज आप बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, आपके मन पर छाए हुए चिंता के बादल हटने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी।

मकर: आज रुका हुआ धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन निवेश के लिए भी दिन लाभकारी है। स्वयं पर विश्वास रखकर ही आज कार्यों को क्रियान्वित करें। आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी।

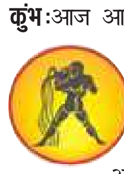

कुंभ: आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आप तन-मन से स्वस्थ होकर कार्य कर पाएंगे। जिससे कार्य में उत्साह एवं ऊर्जा का अनुभव होगा। परिवार के लोगों के सहयोग से आपका मन प्रसन्न रहेगा।

मीन: आज आपका दिन अस्वस्थता और बेचैनी के साथ बीतेगा। किसी का भला करने पर भी आप पर ही विपत्ति आ सकती है, पैसों का लेन-देन न करें। बहनोई और साले से आज लेन-देन न करें।

सू- दोकू क्र.025

	7			4		3		
2			3			9		4
	6			2				
3		1			7		4	
	2			1			6	
8			9		4			1
		2		3		7		
1			7		2	4		3
	5	3		8			7	2

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.24 का हल

9	2	8	3	1	5	7	4	6
4	1	6	8	9	7	2	5	3
7	3	5	4	6	2	8	1	9
2	7	3	9	8	1	4	6	5
5	4	1	6	7	3	9	2	8
6	8	9	2	5	4	1	3	7
3	6	2	7	4	9	5	8	1
8	5	7	1	2	6	3	9	4
1	9	4	5	3	8	6	7	2

शब्द सामर्थ्य -025

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं
1. संघर्ष, दौड़धूप (उर्दू.) 5. सुपुत्र, लायक पुत्र 7. ताकतवर, बलशाली 9. खुशबू, सुरभि, सुगंध 10. अकारण, व्यर्थ, बेवजह 12. गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना 13. यात्रा 15. मृत, जो मर गया हो 16. छोटे कद का, वामन, बौना 18. सांप का सिर, गुण, कला, कौशल 20. निरुत्तर, बेमिसाल 23. गोल हरे दानों वाला एक प्रसिद्ध पौधा, या इस पौधे की फली 24.माता, जननी 25. संतान, औलाद 26. अधीन, अधीनस्थ, कर्मचारी 27. चिड़िया, खग तरफदार।

ऊपर से नीचे
1.पानी में डूबा हुआ, जल प्लावित 2. पाकेटमार, जेब काटने वाला 3. समाधान, खेत जोतने का यंत्र 4. औषधालय 6. युक्ति, उपाय 8. गीला, तर, भीगा हुआ 11. झटके से मुंह से आवाज के साथ हवा बाहर आना, बलगम आदि का बाहर आना 14. तुरंत, झटपट 15. स्त्री, नारी, अबला 17. एक और एक चौथाई 19. आदमखोर 21. दुनिया, संसार, जग 22. वर्ष की छ: ऋतुओं में एक ऋतु जिसमें मौसम सुहावना रहता है 23. बुद्धि, दिमाग।

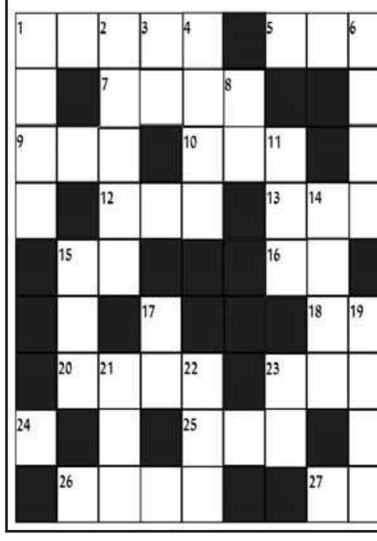

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 24 का हल

पी	चि	दं	ब	र	म			स
ट		भ	ला	ई		अ	स	म
ना	म			स	मा	धि		झ
	ज		बे		न	का	र	ना
बा	बू		आ	य	क	र		
	र	की	ब				प्र	था
ज			रू	प	क		ज	न
हा		पा		ना	म	ची	न	
ज	हां	प	ना	ह		ता	न	ना

उपचुनाव से पहले ग्वालियर-चंबल संभाग को तोहफा, 'चंबल प्राग्रेस वे' का होगा निर्माण

अब चंबल प्राग्रेस वे होगा नाम, सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की बात

उपचुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर-चंबल संभाग को दिया तोहफा

चंबल एक्सप्रेस वे परियोजना का बदला नाम, कहा- जल्द चालू करेंगे काम

ग्वालियर-चंबल के 16 सीटों पर होने हैं उपचुनाव

'चंबल प्राग्रेस वे' होगा नाम

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उसे अब एक नए प्रारूप में शुरू करने जा रहा हूं। इसका निर्माण कार्य 'चंबल प्राग्रेस वे' के नाम से शुरू होगा। साथ ही एक्सप्रेस वे किनारे इंडस्ट्रियल हब भी विकसित किया जाएगा।

जल्द चालू करेंगे काम

सीएम ने कहा कि ये चंबल के विकास का महा पथ बनेगा। महा पथ के दोनों तरफ चुनिंदा जगहों पर औद्योगिक इकाइयां और व्यापारिक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी नितिन गडकरी से अभी इस मुद्दे पर फोन से चर्चा हुई है और हम दोनों बहुत ही जल्दी इस चंबल प्राग्रेस वे का भूमिपूजन करेंगे और काम चालू करेंगे।

ग्वालियर-चंबल संभाग में 16 सीट

मध्यप्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 24 में से 22 सीट कांग्रेस से आए विधायकों के हैं। उपचुनाव वाले 24 सीटों में से 16 सीट ग्वालियर-चंबल संभाग से आते हैं। उपचुनाव के हिसाब से यह इलाका बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी अब पूरी तरह से उपचुनाव के मोड में आ गई है। बीजेपी के आला नेता अब लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। सरकार भी अब चुनावी फैसले लेने लगी है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर-चंबल संभाग को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए चंबल एक्सप्रेस वे को फिर से बनवाने का फैसला लिया है।

दरअसल, शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला लिया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले इसे फिर से बनाने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने मंत्रालय में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया है कि मेरे पिछले कार्यकाल में जो चंबल एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय हुआ था, उसे कांग्रेस की सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। शनिवार को बीजेपी के आला नेताओं ने इस क्षेत्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री ने यहाँ ट्वीट के माध्यम से कहा कि मैंने मंत्रालय में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया है कि मेरे पिछले कार्यकाल में जो 'चंबल एक्सप्रेस वे' बनाने का फ़ैसला लिया था, जिसे कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि यह चंबल के विकास का महा पथ बनेगा, महा पथ के दोनों तरफ़ चुनिंदा जगहों पर औद्योगिक इकाइयाँ और व्यापारिक व्यवस्थाएं बनाई जाएगी।

अधिकारियों ने पूजन कर भौडिया चना केंद्र का किया शुभारंभ

बरेली । मार्केटिंग सोसायटी चना केंद्र क्रमांक 1 आदर्श वेयरहाउस भौडिया पर शनिवार को तहसीलदार राजेश कहार, नायव तहसीलदार सौरभ मालवीय, थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकाती, पत्रकार संघ अध्यक्ष संजय शर्मा, सोसायटी प्रबंधक प्रकाश श्रीवास्तव, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा, गोदाम संचालक खुमान सिंह छेड़ीवाले, सरपंच नरेंद्र धाकड़ द्वारा तुलाई कांटे की पूजन कर खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया उद्घाटन के समय पहुंचे पहले किसान का सैंपल भी सर्वेयर द्वारा से तिवड़ा होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया । प्रबंधक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि तिवड़ा की समस्या के कारण केंद्रों पर चना नहीं आ पा रहा सरकार के स्पष्ट निर्देश है शून्य प्रतिशत तिवड़ा भी नहीं होना चाहिए जिससे किसान परेशान भी हैं इस बीच केन्द्र पर काम कर रहे हैं हिम्मालो को तहसीलदार एवं थाना प्रभारी ने कोराना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिग एवं मार्क्स का पालन करने की अपील की ।

किसानों के हित मे पूर्व बिधायक रामकिशन पटेल लगातार कर रहे गेहू केंद्रों का निरीक्षण

बरेली । उदयपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक रामकिशन पटेल लगातार उदयपुर विधानसभा के गेहूं खरीदी केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं केंद्रों पर किसानों द्वारा बताई जा रही समस्याओं के बारे में तत्काल कलेक्टर एक संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं जिससे किसान परेशान ना हो साथ पूर्व बिधायक ने कहा कि चने की जो तुलाई में ओर गेहू के ट्रांसपोर्ट में जो परेशानी आ रही है जल्द से जल्द इस परेशानी से निजाद दिलाई जाएगी समय बिपरीत चल रहा है किन्तू हमारे मध्यप्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसान भाईयों के हित मे पहले भी कार्य करते आये है और आगे भी करते रहेंगे और किसानों के हित मे ही दिन रात सोचते रहते है ।

बीजेपी नेताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली मीटिंग, उपचुनाव की हुई प्लानिंग?

24 विधानसभा सीटों के विस्तारकों के साथ हुई चर्चा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी थे मौजूद

उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के हैं 22 सीट

सकारात्मक रही चर्चा

वहीं, बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि संकट की इस घड़ी में बीजेपी के सभी साथी प्रदेश की सेवा में लगे हैं। आज साथियों से हुई चर्चा भी बहुत सकारात्मक रही।

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी के आला नेताओं की यह बैठक हुई है। इससे पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने स्तर पर संगठन के लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे।

ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। यह पहला मौका है, जब सिंधिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी बीजेपी नेताओं के साथ जुड़ें। इस बैठक में प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत शामिल हुए। बैठक में सभी आला नेताओं ने उपचुनाव वाले 24 विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारकों के साथ चर्चा की।

जानकारी के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीधे 24 विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारकों से सीधी चर्चा की। सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ही नेताओं को निर्देश देते रहे हैं। मीटिंग के दौरान पार्टी ने स्थानीय नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के 22 विधायकों के साथ पूरे दम से चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्हें साफ कर दिया गया है कि आप सभी लोग चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाएं।

मुझे अपनी टीम और कार्यकर्ता साथियों की सेवा भावना पर गर्व है। जनकल्याण और सेवा के लिए समर्पित हमारे साथी घर-घर तक पहुंचेंगे और प्रदेश को इस संकट के पार ले जाएंगे।

24 सीटों पर हैं उपचुनाव

दरअसल, पार्टी ने पिछले दिनों यह स्पष्ट कर दिया है कि उपचुनाव में 22 सीटों पर सिंधिया के लोग ही उम्मीदवार होंगे। उपचुनाव 24 सीटों पर होने हैं, 2 सीट पूर्व से खाली है। चर्चा है कि सिंधिया के लोगों को स्थानीय बीजेपी नेताओं से सहयोग नहीं मिल रहा था। उसके बाद पार्टी एक्टिव हुई और तैयारी में जुट गई है। 24 में से ज्यादातर सीटें ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग के हैं। ऐसे में बीजेपी अब कोई चूक नहीं करना चाहती है।

कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए

नर्मदा से अवैध तरीके से रेत उत्खनन करने वालों पर धारा 307 के तहत दर्ज करें मामला

नर्मदा नदी में अवैध तरकी से रेत उत्खनन करने वालों पर नर्मदा की हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नर्मदा नदी में रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर नर्मदा की हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि नर्मदा हमारी जीवनदायिनी नदी है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मां नर्मदा को एक जीवित इकाई माना गया है तथा ये हमारी श्रद्धा का केन्द्र है। इसलिए मां नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ शंकर है। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदे हर, जिंदगी भर। उन्होंने कहा कि नर्मदा से जेसीबी जैसी किसी भी प्रकार की मशीन से उत्खनन किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है तथा समय-समय पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (हृत्रञ्) एवं अन्य न्यायालयों ने भी सभी नदियों में मशीनों से उत्खनन करने पर रोक संबंधी आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इसलिए मैंने नर्मदापुरम एवं जबलपुर संभागों के 11 जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नर्मदा की छाती छलनी कर रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर मां नर्मदा की हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर उसी प्रकार कार्रवाई की जाये, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की हत्या का प्रयास करने में होती है। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के उन जिलों के अधिकारियों को भी शीघ्र पत्र लिखूंगा, जिन जिलों से होकर यह नदी गुजरती है और उनको भी निर्देश दूंगा कि जो लोग अवैध तरीके से मशीनों के माध्यम से नर्मदा में रेत उत्खनन कर रहे हैं, उन पर मां नर्मदा की हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज किया जाए। मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इसके अलावा, हमने निर्देश दिए हैं कि मशीनों से किए जा रहे उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन स्थलों पर सघन निगरानी रखी जाए तथा जिन रास्तों से होकर रेत का परिवहन किया जाता है ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जरूरतमंदो को अनाज सामग्री का किया वितरण,सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की कही बात

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। साध्वी प्रज्ञा सिंह सांसद भोपाल के निर्देश अनुसार संचालित की जा रही सांसद रसोई जिस का संचालन कोलार हिंदू उत्सव समिति के सचिव वर्तमान पार्षद रविंद्र यति , लखन मेहरा , महेश मनमानी , राजा तवर रामेश्वर अग्रवाल, एवं उनकी पूरी टीम के माध्यम से किया जा रहा था। समापन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस सुखाड़िया , मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल एवम भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी , विजय अटवाल सांसद रसोई में अतिथि के रुप में उपस्थित रहे। सांसद रसोई विगत 15 दिनों से लगातार चल रही हैं जिसमें प्रतिदिन 600, श्रमिकों प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट की व्यवस्था की जाती थी। विगत 15 दिनों में लगभग 8000 ऐसे मजदूरों को भोजन के पैकेट की व्यवस्था की गई। समापन के अवसर पर ऐसे निर्धन! असहाय मजदूर जो बेचारे तपती गर्मी में नंगे पैरों चल रहे थे। ऐसे मजदूरों को प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा एवं कमल पटेल जी द्वारा स्वयं अपने हाथों से उनको, चरण पादुका पहनाकर एवं, आशा की के इस महामारी में हम सदैव तत्पर रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस महामारी में आमजन के साथ हैं। भाजपा प्रदेश विष्णु दत्त शर्मा ने लोगों को समझाइश दी की आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सब्जी को खरीदने के बाद गर्म पानी में रखे बाद में उसको अचछे तरह से धोए। और कोरोना से बचने के लिए जिला प्रशासन के नियमों का पालन करे।

भोपाल में पालतू कुत्ते के साथ पहुंचे क्वारैंटाइन सेंटर

नव प्रदेश संवाददाता

भोपाल। राज्य अपडेट टीकमगढ़ के बाद रविवार को भोपाल में भी एक परिवार अपने साथ पालतू कुत्ते को लेकर क्वारैंटाइन सेंटर पहुंचा है। ये परिवार जहांगीराबाद इलाके का है। क्वारैंटाइन सेंटर में ले जाने से पहले सूची में जैकी का नाम भी शामिल किया गया। परिवार के साथ ही जैकी का नाम लिखकर परिवार को महावीर मेडिकल कॉलेज का कमरा नंबर आठ आवंटित किया गया। जहां यह परिवार 3 दिन से रह रहा है। इतना ही नहीं जैकी के नाम से एक अलग खाने का बाक्स दिया जाता है, ताकि क्वारंटाइन जैकी भूखा न रहे। पहले तो इसके लिए अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन कोराना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए परिवार को क्वारंटाइन करना जरूरी था, क्योंकि एक ही बिल्डिंग में 10 परिवार के 40 लोग रहते थे। लिहाजा डॉगी को भी साथ ले जाने की अनुमति दी गई।

किसानों की समस्याओं और तहबाजारी की अवैध वसूली को लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

बरेली । शनिवार को युवा कांग्रेस नेताओं ने किसानों को खरीदी केंद्रों पर हो रही समस्याओं एवं छोटे व्यापारियों के साथ हो रहें छलावा को लेकर अनुविभागीय अधिकारी बृजेन्द रावत को ज्ञापन सौंपकर कहा कि कोरोना महामारी के संकट के काल में भी छोटे छोटे व्यापारियों से तहबाजारी के नाम से की जा रही अवैध वसूली जायज नहीं है साथ ही चने में नाम मात्र तीबडा होने पर भी खरीदी नहीं की जा रही है जिससे किसान परेशान हैं कांग्रेसियों ने एसडीएम जल्दी समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया है वहीं एसडीएम बृजेंद्र रावत ने भी कहा कि तय बजारी पूर्णता बंद है अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करेंगे ज्ञापन सौंपने मे युवा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह, युवा कांग्रेस नेता ज्ञानेंद्र राजपूत, कमलनाथ विचार सद्भावना मंच जिला अध्यक्ष खालिद ठेकेदार, कमलनाथ विचार सद्भावना मंच के जिला उपाध्यक्ष सोनू धाकड़, युवक कांग्रेस के नगर मंडल अध्यक्ष राजा भार्गव, युवा समाजसेवी अनिल गुप्ता, बंटी भैया ,छोटू भाई उपस्थित रहे ।

कृषि उपज मंडी अधिनियम अध्यादेश 2020 को रद्द करने बरेली मंडी कर्मचारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

नव प्रदेश संवाददाता

बरेली । मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम अध्यादेश 2020 को रद्द करने के संबंध में आज कृषि उपज मंडी के समस्त कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम बृजेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपा ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने मांग की है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश में कृषकों एवं मण्डीयों में संबंधित अधिकारियों के अधिकारों उनके हितों एवं उनकी जीवका उपार्जन को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 क्रमांक 24 सन 1973 लागू है उक्त अधिनियम लागू हुए तकरीबन 48 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उक्त अधिनियम की मूल मनसा कृषकों की कृषि उपज की नीलामी करवा कर उनको सही तोल एवं तुरंत मूल का भुगतान करवाना है । जो वर्तमान तक यथोचित अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है यही कारण है कि कृषकों को उनकी उपज का भुगतान मिलता आ रहा है और मंडी या उनके भुगतान तोलमोल में नियंत्रण करने में सक्षम भी रही हैं उक्त अधिनियम को बदलने संशोधन करने या रद्द करने की मांग किसी भी कृषक संगठन ,मजदूर संगठन ,व्यापारी संगठन तथा कर्मचारी संगठन द्वारा आज दिनांक तक राज्य शासन या केंद्र शासन से नहीं की गई । निजी मंडी के क्रियाकलापों में मंडी बोर्ड मंडी प्रशासन के हस्तक्षेप को निषेध रखा गया है जिससे कृषक को उत्पादकों का शोषण होना स्वाभाविक है यह कि उक्त अध्यादेश अनुसार धारा पांच के अधीन निजी प्रांगण की स्थापना होने पर पूर्व में स्थापित शासकीय मंडियों का प्रभावित होना निश्चित है ऐसी स्थिति में मंडी समिति सेवा राज्य मंडी बोर्ड सेवा एवं मंडी बोर्ड सेवा के अधिकारी कर्मचारियों का भविष्य समाप्त होता प्रतीत हो रहा है उनके वेतन भत्तों उनके द्वारा की गई वर्षो की सेवा उपरांत उनको मिलने वाला परिलाभ पेंशन आदि की अनिश्चितता विद्यमान हो रही है जिससे कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैरान परेशान होकर मानसिक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं । वहीं उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां मात्र अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का कार्य करती हैं उन्होंने किसानों के हितों से कोई लेना-देना नहीं रहता पूर्व के वर्षो में विभिन्न मंडी समितियों में बहुराष्ट्रीय तथा निजी कंपनियों द्वारा अनेक घोटाले किए हैं तथा किसानों का शोषण किया है उदाहरण के रूप में राजधानी की मंडी भोपाल में फार्म एडब्ल्यूबी (ऑस्ट्रेलियन बीट बोर्ड) द्वारा लगभग 72 लाख का घोटाला किया है जिसका प्रकरण आज भी माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है इसी तरह फॉर्म वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी लाखों रुपए के घोटाले किए गए ।.

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक यशवंत धोटे द्वारा श्री बालाजी प्रिंटर्स प्लाट नंबर-3, नेशनल प्रेस एरिया, लिंक रोड नं-3 ,पत्रकार कॉलोनी के पास से मुद्रित कर, ई-2/237 अरेरा कालोनी भोपाल से प्रकाशित, प्रबंध संपादक डॉ. शिशिर उपाध्याय,
फोन नं : 0755-2465533, मो. 9039005699 (न्याय क्षेत्र भोपाल), MPHIN/2017/72749 email:navpradeshbhopal@gmail.com